[Dr. R. K. Chakrabarty]
This is not the way to improve the condition of the country. We will have to have something concrete and take care of this population factor and the foodgrains factor. Also the total trade in foodgrains in the whole country must be taken under Government control and the people, especially the rural people, must be assured of a minimum quantum of foodgrains every week, every month, throughout the year.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2.00 P.M.

The House then adjourned for lunch at fifty-eight minutes past twelve of the clock.

The House reassembled after lunch at two minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman, Shri V. B. Raju,** in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN: Shri Indradeep Sinha.

REFERENCE TO SITUATION IN KURUKSHETRA

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं सरकार का ध्यान एक तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एक बजे के करीब जब मैं आ रहा था तो मुझे सूचना दी गई कि कल कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री जयप्रकाश जी की एक आम सभा है, लेकिन श्री बंसी लाल की सरकार ने वहां पर तमाम पुलिस भेज दी है *Interruption* सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सब स्थानों पर पुलिस तैनात कर दी गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस सरकार को कहें और यह सरकार इस बात की व्यवस्था करे कि वहां पर कोई अन डेमोक्रेटिक काम न हो *Interruption* । हमने श्री रणवीर सिंह से कहा कि आप श्री बंसी लाल को फोन करो कि श्री जय प्रकाश जी की मीटिंग ठीक प्रकार से हो। वहां पर स्थिति यह है कि सब लाउडस्पीकर बन्द कर दिए गये हैं, धारा 144 लागू कर दी गई है और सभी कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे पोस्टरों को फाड़ दिया गया है . . *(Interruption)* यह सब क्यों हो रहा है? इस प्रकार से श्री बंसी लाल की सरकार नहीं चल सकती है।

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : अभी वहां पर ऐसेम्बली का सैशन हो रहा है।

श्री राजनारायण : वहां पर हजारों कार्यकर्त्ता बन्द कर दिये गये हैं।

उप सभाध्यक्ष (श्री वी. बी. राजू) : श्री राजनारायण जी, अब आप बैठ जाइये।

DISCUSSION UNDER RULE 176 DISCUSSION RE. WIDESPREAD SCARCITY AND FAMINE CONDITIONS IN SEVERAL PARTS OF THE COUNTRY—CONTD

श्री इन्द्रदीप सिंह (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज देश के अनेक भाग में अभाव, अकाल और सूखे की स्थिति है। वह बड़ी गम्भीर है। अखबारों में प्रकाशित होने वाले तथ्यों को एकत्रित करके देखा जाय तो पता चलता है कि हमारे देश के आधा दर्जन से अधिक राज्यों में आज अत्यन्त शोचनीय स्थिति फैली हुई है। आसाम के ग्वालपाड़ा जिले में 92 फीसदी से अधिक लोग अकाल से प्रभावित हैं और वहां पर अखबारों में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार तीन लाख से अधिक लोग घास और पत्ते खाकर जी रहे हैं। गुजरात के 18,000 में से . . .

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal): Where is the senior Minister, Mr. Jagjivan Ram?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P SHINDE): He is coming.

श्री इन्द्रदीप सिंह : गुजरात के कुल 18,000 गांवों में से 13,000 गांव प्रभावित हैं। पड़ोसी राज्य हरियाणा में 2 जिलों में अभाव की स्थिति है—महेन्द्रगढ़ और भिवानी में—और अखबारी रिपोर्टों के अनुसार लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश में काफी बड़ा हिस्सा अभाव से पीड़ित है। उड़ीसा में, जो अखबारों

में समाचार निकले हैं, उनसे मालूम होता है कि इस शताब्दी का सबसे भयंकर अकाल और अभाव फैला हुआ है और 2478 ग्राम पंचायतों को उड़ीसा सरकार ने अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। राजस्थान में लगभग 2 करोड़ जनसंख्या प्रभावित है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिले प्रभावित हैं और पश्चिम बंगाल में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ से ज्यादा लोग, वहां की लगभग एक-चौथाई जन-संख्या, प्रभावित है। इस प्रकार, महोदय, देश के अनेक हिस्सों में, आधे दर्जन से अधिक राज्यों में, अभाव की स्थिति है, और यद्यपि सरकार की ओर से बराबर इसका खण्डन किया गया है लेकिन अखबारों में खबरें आती रहती हैं कि कुछ लोगों की भूख से मृत्यु भी हो गई है। मैंने पढ़ा है, कृषि मंत्री ने यहां पर भी, लोक सभा में, इस बात का खंडन किया है और कहा है कि सरकार की ओर से पता लगाया गया और ये खबरें निराधार पायी गई हैं। निराधार खबरें भी अक्सर उड़ायी जाती हैं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि जब भी भूख से मौत की खबरें आती हैं और सरकार की ओर से जांच की जाती है तो जांच-रिपोर्ट में आता है कि वह व्यक्ति कमजोरी के कारण मर गया, कै-दस्त होने के कारण मर गया। इस प्रकार की खबरें आम तौर से जो सरकारी रिपोर्ट में आती हैं उनसे मिलती हैं। जो भी हो, वह मृत्यु भूख और अभाव से हुआ करती है क्योंकि अभाव या अकाल कोई सांप नहीं है कि आकर एक दिन काट लेता है। धीरे धीरे शरीर की शक्ति समाप्त हो जाती है और एक दिन वह व्यक्ति मर जाता है और मरने के समय उसे कोई न कोई बीमारी हो जाती है। लेकिन अगर निष्पक्षतापूर्वक इन तथ्यों पर विचार किया जाए तो हमें मानना पड़ेगा कि ये अभाव और अकाल की मौतें हैं और इस प्रकार की मौतें हो रही हैं यह काफी चिंता की बात है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति हमारे देश में दुर्भाग्यवश अक्सर पैदा हो जाया करती है और इसके पीछे कई तथ्य हैं, कुछ मानवीय हैं कुछ दैवी हैं। मैं दैवी तथ्यों की ओर इशारा नहीं करूंगा क्योंकि पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी हम बराबर इस पर चर्चा कर चुके हैं—कहीं बाढ़ आ जाती है कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं वर्षा का अभाव हो जाता है और इन कारणों से अभाव या अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। तो हर साल कुछ न कुछ इलाका बाढ़ या सूखे से पीड़ित रहता है। दुर्भाग्यवश, अभी हमारा देश या उसकी सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि कह सके कि हमने बाढ़ और सूखे से बचाव की गारण्टी कर ली है। गारण्टी करने की स्थिति में हम नहीं हैं। तो बाढ़ और सूखे के रहते हुए भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इस प्रकार की दुस्सह परि-स्थिति देश के किसी हिस्से में पैदा नहीं हो। उसके लिए प्रथम आवश्यकता इस बात की है कि खेती की पैदावार ऐसी हो, खास कर अनाज की पैदावार ऐसी हो, कि कहीं इस प्रकार की अभाव की स्थिति पैदा न हो। कुछ दिनों पहले अग्रिकल्चरल प्राइसेस कमीशन ने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि चौथी पांच-साला योजना में जो 11 करोड़ 40 लाख टन, यानी 114 मिलियन टन खाद्यान्न की पैदावार का लक्ष्य रखा गया था, वह प्राप्त नहीं हुआ है। और 1973-74 में कितनी पैदावार हुई इस बारे में सरकारी तौर पर आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं, लेकिन अनुमान यह है कि 104 या 105 मिलियन टन से ज्यादा अनाज पैदा नहीं हुआ है। हमारे देश में जन संख्या हर साल बढ़ती जाती है और अगर अनाज की पैदावार में वृद्धि नहीं होती है तो इसके कारण देश में अनाज की कमी हो जाती है। लेकिन सिर्फ थोड़ी सी कमी हो जाने से इस तरह की स्थिति पैदा हो जाय कि कुछ लोगों को खाने को न मिले, कुछ लोग भूख से मर जायें, भीख मांगने के लिये मजबूर हो जायं, यह आवश्यक नहीं है। यह स्थिति इस कारण पैदा हो गई है कि देश में जो भी अन्न पैदा होता है उसका संग्रह और वितरण सरकार को अच्छी तरह से करना चाहिये, वह सरकार ने नहीं किया है।

उप सभाध्यक्ष महोदय, एक साल पहले सरकार ने गेहूं का थोक व्यापार अपने हाथ में लिया था। उस समय यहां पर हमारे मित्र बैठे नहीं हैं, अनेक दलों के मित्र हैं, उन लोगों ने बहुत शोरगुल मचाया था, हंगामा किया

[श्री इन्द्रदीप सिंह]

था कि सरकार ने गेहूं का थोक व्यापार अपने हाथों में ले लिया है और यही कारण है कि सरकार को अनाज नहीं मिला तथा बाजार से गायब हो गया और कीमतें बढ़ गईं। मैं समझता हूं कि इन्हीं लोगों के शोरगुल की वजह से सरकार घबरा गई और उसने उनके सामने आत्मसम्पर्ण कर दिया और इस साल गेहूं का थोक व्यापार बड़े बड़े व्यापारियों के जिम्मे सौंप दिया। इन व्यापारियों ने सरकार को विश्वास दिलाया था कि हम इस साल आप को 50 लाख टन गेहूं दे देंगे। उसने इस बारे में जो एग्रीमेन्ट मुकर्रर किये उन्होंने यह आश्वासन दिलाया कि इससे भी ज्यादा गेहूं सरकार को दे दिया जायेगा। सरकार ने जो यह प्रयोग किया वह बिल्कुल ही असफल साबित हुआ। सरकार को केवल 17-18 लाख टन ही गेहूं इस साल मिला और इससे ज्यादा गेहूं सरकार को प्राप्त नहीं हो सका बल्कि मंडियों में भी गेहूं नहीं आया। सरकार की ओर से जो प्रकाशित आंकड़े हैं उसके हिसाब से 1973-74 में यानी पारसाल 40 लाख टन गेहूं मंडियों में आया और 43-44 लाख टन गेहूं सरकार ने खरीदा। इस साल मंडियों में 31 लाख टन गेहूं आया और 17-18 लाख टन गेहूं सरकार ने खरीदा। ये आंकड़े 24 अगस्त तक के हैं और इसके बाद के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। जब सरकार ने गेहूं का थोक व्यापार अपने हाथ में ले लिया था तो जो बड़े बड़े व्यापारी थे, जो उनके दोस्त थे, उनके सहयोगी और समर्थक जितने राजनीतिक दल थे, उन लोगों ने हिन्दुस्तान भर में शोरगुल मचाया, यह हंगामा मचाया कि सरकार ने एक गलत काम किया है। उस समय भी सरकार ने इन अड़चनों के बावजूद 44 लाख टन गेहूं प्राक्योर किया था जिस के कारण पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को जारी रखा जा सका। लेकिन इस साल तो गेहूं का व्यापार सरकार ने थोक व्यापारियों के हाथ में दे दिया और उनकी भलमनसाहत और आश्वासन पर भरोसा किया। उन्होंने सरकार को यह भरोसा दिलाया था कि वह गेहूं सरकार को दे देंगे, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार को गेहूं नहीं मिला और दाम भी इतने बढ़ गये जितने कि पिछले वर्षों में कभी भी नहीं बढ़े थे। गेहूं के भाव सरकार ने 105 रुपया क्विंटल रखा था, और व्यापारियों ने 10-20 रुपया ज्यादा देकर सारा गेहूं खरीद लिया और अब वह गेहूं बाजार में 300, 400 और 500 रुपया क्विंटल में बिक रहा है। हमें इस बात का आश्चर्य होता है कि जितने भी राजनीतिक दल के लोग थे, जिन्होंने सरकार से आग्रह किया था कि गेहूं का थोक व्यापार उसको छोड़ देना चाहिये, हम तुम को गेहूं दिलवा देंगे, वे आज इस बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं, वे लोग चुपी साधे हुए बैठे हैं। वे लोग इस महंगी का बहाना बनाकर असेम्बली भंग करने की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट का घेराव करने की बात कर रहे हैं और आल इंडिया रेडियो का घेराव करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के जो राजनीतिक दल वाले लोग हैं, इन लोगों की इस बारे में एक साजिश है। हमारी सरकार से यह शिकायत है कि उसने इन लोगों की साजिश के सामने आत्मसम्पर्ण कर दिया है जिसके कारण भुखमरी हो रही है और लोगों को परेशानी हो रही है तथा सरकार को विदेशों में जाकर गेहूं के लिये दरवाजा खट-खटाना पड़ रहा है और ऊंचे दामों पर गेहूं खरीदना पड़ रहा है।

मैं विश्वास करता हूं कि अभी भी जिस रेट पर हमारे देश में गेहूं सरकारी दूकानों पर मिलता है उससे ज्यादा दाम पर सरकार को विदेशों से खरीदना पड़ता है और फिर सबसिडी देनी पड़ती है। ये सब परेशानियां इस कारण पैदा हो रही हैं कि सरकार ने थोक व्यापार को त्याग दिया और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया।

अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री ने दूसरे सदन में बोलते हुए एक और तथ्य को स्वीकार किया है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बहुत सा अनाज बड़े बड़े जमींदारों और भूमिदारों ने छिपा कर रख लिया है।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा (उत्तर प्रदेश) : वह रणबीर सिंह के पास होगा।

श्री इन्द्रदीप सिंह : पता नहीं किन-किन के पास होगा । बहुत से लोगों के पास होगा । कृषि मंत्री ने नहीं कहा है :—

> The shortage was not as much as it was shown to be because the rich farmers were holding on to their stocks in the expectation that they would get a higher price". (Synopsis of Debates—Page 90)

यह कृषि मंत्री ने खुद स्वीकार किया है । कृषि मंत्री ने इस बात का दावा किया कि हमने इस छिपे हुए अनाज को पकड़ने के लिए जो अभियान चलाया है उसमें एक लाख टन अनाज पकड़ा है ।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : कोलखोंज बनवाइए।

श्री इन्द्रदीप सिंह : कोलखोंज (सामूहिक खेती) बनवानी पड़ेगी एक दिन । एक लाख टन अनाज आपने निकाला लेकिन कितना छिपा कर रखा हुआ है ? मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कुछ अनुमान तो बताए कि कितना छिपा कर रखा हुआ है । जैसा कि एक सदस्य ने कहा, 55 हजार छापे मारे गए और एक लाख टन अनाज मिला । एक छापे पर कितना एवरेज पड़ा यह आसानी से निकाला जा सकता है । इससे पता चलेगा कि यह बहुत छोटी मात्रा है । छापों में क्या होती है ? छापे से पहले पुलिस अधिकारी गल्ला चोरों को खबर दे देते हैं कि तुम्हारे यहां छापा मारने आ रहे हैं । छापा मारने का काम या छिपा हुआ अनाज निकालने का काम तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसमें जनसहयोग न लिया जाय ।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : सी. पी. आई का सहयोग लिया जाये ।

श्री इन्द्रदीप सिंह : आपका भी सहयोग हम लेने के लिये तैयार हैं बशर्ते कि आप गल्ला-चोरों की ओर न होकर जनता की ओर हों । हम सरकार से कहेंगे कि जनता की ओर जितने दल के लोग हों उनका सहयोग ले, लेकिन जो लोग गल्ला चोरों के कान में बताएंगे कि तुम्हारे यहां रेड होने वाला है उनका सहयोग नहीं लेना चाहिये । इसलिए मेरी स्पष्ट राय है कि जो भी दल गल्ले के थोक व्यापार के पक्ष में नहीं हैं उनको अन्न सलाहकार समितियों में नहीं बैठने देना चाहिये क्योंकि वे तो बुनियादी नीति के ही विरुद्ध हैं । इन समितियों में उन्हीं लोगों को रखना चाहिए जो गल्ले के थोक व्यापार को सरकार के हाथ में रखने और सरकारी दुकानों के माध्यम से अनाज और दूसरी उपयोगी वस्तुओं के वितरण की सरकारी नीति के पक्ष में हों । उनको लेकर सलाहकार समितियां बनानी चाहिए और उनके हाथ में यह काम दिया जाय तो जितना छिपा हुआ स्टाक है वह खोज कर निकाला जा सकता है और अभावग्रस्त जनता के पास पहुंचाया जा सकता है ।

एक और विषय की चर्चा अन्न मंत्री ने लोकसभा में की है । दो वाक्य उनके मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूं ।

> "The conditions that existed today were the accumulation of the economic and social conditions that existed in the country for years. It had not been possible to disentangle ourselves from the inequitous social set-up in the country that affected agricultural production as well".

अन्न मंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि देश में जो असमानता की स्थिति फैली हुई है वह आज की नहीं है बल्कि अनेक वर्षों से विद्यमान है और सरकार उसको दूर करने में सफल नहीं हुई है । जिस कूटनीतिक शब्दावली का इस्तेमाल अन्न मंत्री महोदय ने किया है उससे निकल कर साफ शब्दों में हम कहते हैं कि गांव के अन्दर मुट्ठी भर भूस्वामियों के हाथ में जो जमीन का केन्द्रीयकरण है जबकि अधिकांश लोग भूमिहीन हैं या उनके पास बहुत कम जमीन है यही प्रधान कारण है अन्न संकट का । जमीन के इस केन्द्रीकरण के कारण गांव में मुट्ठी भर लोगों के हाथों गरीबों का शोषण हो रहा है और अनाज की पैदावार भी घटी है । जो अनाज पैदा होता है उसको ये लोग छिपा कर रख लेते हैं और जब तक चोर-बाजार का दाम नहीं मिलता उस अनाज को बाजार में आने नहीं देते ।

[श्री इन्द्रदीप सिंह]

यह आश्चर्य की बात है कि कृषि मंत्री स्वीकार करते हैं कि यहां यह परिस्थिति है और वर्षा से बनी हुई है और हम इस परिस्थिति को दूर नहीं कर सकते, तो आप क्यों हैं वहां पर ? अगर यह परिस्थिति है और वर्षा से बनी हुई है और आप जानते हैं कि इसको दूर नहीं कर सकते तो आप क्यों वहां बैठे हुए हैं ?

श्री ओम प्रकाश त्यागी (उत्तर प्रदेश) : क्योंकि आपकी हमदर्दी है ?

श्री इन्द्रदीप सिंह : हमारी हमदर्दी यह है कि हम उनकी आंख में उंगली डालकर बतलाना चाहते हैं कि आपको यह काम करना होगा। नहीं करेंगे तो उनको हटाकर हम उन लोगों को वहां बैठाना चाहते हैं जो इसको कर सकें और उन लोगों में आप लोग नहीं हैं, क्योंकि आप लोग उनके साथ हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है। आप जमीन को समेटकर बैठे हुए हैं।

श्री रणवीर सिंह : जो लाठी दल है वह भी उसमें नहीं है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : सी. पी. आइ. उसमें है क्योंकि सी. पी. आई. माने चमचा पार्टी आफ इंडिया।

श्री इन्द्रदीप सिंह : हम इंडियनों की जनता की पार्टी है, गल्ला चोर की चमचा पार्टी नहीं। गल्ला चोर और नफाखोर की पार्टी को उरा सरकार में नहीं होना चाहिए।

उप-सभाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं अन्त में निवेदन करूंगा कि सरकार को अभी भी इस सुस्ती को त्यागना चाहिए और इतना बड़ा अभाव जो फैला हुआ है, इस प्रकार की भुखमरी जो फैली हुई है, देश में इतना असन्तोष जो फैला हुआ है, उसको सामने रखकर अभी भी भूमि सुधारों को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिये कदम उठाने चाहिए। अभावग्रस्त क्षेत्रों में भूमिसुधारों से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि भूमि सुधार होगा उसके बाद अनाज की पैदावार बढ़ेगी, उसके बाद गरीबों के घर में आनाज होगा। तो आज तत्काल आवश्यकता है कि जितने भी अभावग्रस्त क्षेत्र हों वहां पर शीघ्र से शीघ्र अनाज पहुंचाया जाए और जितना भी अनाज छिपाकर रखा हुआ है उसके लिए एक देशव्यापी अभियान चलाकर तमाम छिपे हुए गल्ले को निकाला जाये।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अखबारों में हमने पढ़ा कि यहां पर कुछ दोस्त लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए, आल इंडिया रेडियो का घेराव करने के लिए मैं सरकार से और शासक दल से कहूंगा कि आप नारा दीजिए 'गल्ला चोरों का घेराव करो' और जय प्रकाश नारायण से कहें कि अगर गरीबों के लिए कोई मोहब्बत तुम में है तो तुम हम चलते हैं नफाखोरों और गल्ला चोरों का घेराव करने के लिए तुम हमारा साथ दो।

धन्यवाद।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (राजस्थान) : उप-सभाध्यक्ष जी, इन पिछले वर्षों से कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि अकाल हमारे देश का एक अंग बन गया है। पहले तो हम यह सोचा करते थे कि शायद राजस्थान ही एक ऐसा अभागा प्रांत है जहां पर दूसरे तीसरे साल अकाल पड़ जाता है। लेकिन अकाल आजकल हमारे देश का एक अंग सा बनता जा रहा है। सबसे ताज्जुब इस बात को लेकर होता है कि जिस देश में दुनियाभर के पानी का 10वां हिस्सा हो, उसमें हर साल अकाल कैसे पड़ जाता है। दूसरा हमारे यहां की जो नदियां हैं वह हर साल 1,350 एकड़ फीट पानी बहाकर समुद्र में ले जाती हैं और हम अपने यहां जो पानी के सोर्सेज हैं उनका तीसरा हिस्सा मुश्किल से इरिगेशन सिंचाई के लिए काम में ला सकते हैं, बाकी सारा का सारा पानी बेकार समुद्र में बहकर चला जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि इधर हमारे यहां फ्लड हर साल किसी न किसी रूप में 2-3 राज्यों में आते रहते हैं और बाढ़ से जो नुकसान होता है उसका मोटे तौर से हम हिसाब लगाएं तो 120 करोड़ रुपए का नुकसान चाहे फसल की नजर से हो, चाहे मिल्कियत की नजर से हो, हर साल हो जाता है और जान का नुकसान उसके अलावा

होता है। तो जब हमारे मुल्क में इतना पानी है, इतने फ्लड होकर नुकसान होता है, इतनी ज्यादा मात्रा में पानी समुद्र में चला जाता है, अगर उसी पानी का हम ठीक ढंग से सदुपयोग कर सकें, उसे सिंचाई के लिए काम में ला सकें तो समझ में नहीं आता कि हिन्दुस्तान में कोई अकाल कैसे रह सकता है। रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अब दुर्भाग्यवश स्थिति यह है कि आज 72 जिलों में अकाल पड़ा हुआ है। एक नहीं कई राज्यों में मिल कर आन्ध्र, हरियाणा, बिहार, राजस्थान इत्यादि में 13 राज्य आज अकाल की चपेट में हैं। मैं आपको एक नम्र सुझाव देना चाहती हूं कि हमारे पास जो एक विशाल जलाशय है उसके लिए हम अपनी एरी प्लानिंग पूरी ताकत अपने पूरे रिसोर्सेज इसके सदुपयोग के लिए लगाएं और कामों को छोड़ दें।

आज हमारे मुल्क के सामने सबसे कठिन परिस्थिति जो है वह अन्न की है। आज हमारे मुल्क के सामने सब से बड़ी समस्या जो है वह अन्न की बढ़ती हुई कीमतों की। अगर इन दोनों चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं तो मैं समझती हूं इस वक्त हमारे सामने कोई दूसरी समस्या नहीं रह जाएगी। जब हम अपने पानी के रिसोर्सेज के बारे में सोचते हैं तो फंड की बात आती है। मैं मानती हूं कि इसमें बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता है। इसके अलावा हम लोगों की अपनी भी कुछ खामियां हैं, कमजोरियां हैं। आज कई प्रोजेक्ट हमारे हाथ में हैं। आज बहुत सी नदियों की प्लानिंग हम लोगों ने कर रखी है। नर्मदा, गोदावरी, कावेरी और पार्वती आदि नदियों की प्लानिंग हमने कर रखी है। लेकिन आपस के राज्यों के झगड़ों में वे डिस्प्यूट में पड़ी हुई हैं। एक नहीं बड़े-बड़े प्रोजेक्ट 10 साल से चले आ रहे हैं, 15 साल से चले आ रहे हैं अगर हम उन डिस्प्यूट को सुलझा सके होते उनको उस वक्त दबा दिया होता तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती।

नर्मदा का झगड़ा आज तीन राज्यों के बीच में है वह पता नहीं कब का पड़ा हुआ है। इसी तरह कृष्णा का एवार्ड मिल गया लेकिन फिर भी उसमें झगड़ा चल रहा है। इसी तरह कावेरी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में झगड़ा है। गोदावरी को लेकर महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में झगड़ा चल रहा है। माही को लेकर राजस्थान और गुजरात में झगड़ा है, यह कोई नहीं कह सकता कि केन्द्रीय सरकार भी यह नहीं कह सकती कि यह कोई बाहर का मामला है इसलिए हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि यह मामला हमारे अपने राज्य के बीच में है इनका समझौता हमें कर लेना चाहिए, वाटर डिस्प्यूट को खत्म करना चाहिए। मैं तो यह कहूंगी कि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनको नेशनलाइज किया जाए ताकि इन राज्यों के बीच के झगड़े खत्म हों। केन्द्र के पांच आदमी बैठकर, जैसा ठीक समझें उसे सुलझा सकते हैं। आप जानते हैं इनके सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है। उनमें लाखों-करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। बड़ी-बड़ी, ऊंची तनख्वाहों के आदमी उनमें हैं, वकील लाए जाते हैं, केन्द्र का अनाप-शनाप पैसा उसके लिए खर्च होता है और उसका नतीजा यह निकलता है

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: The Chair feels that tribunals don't find solutions.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत: मैं मंत्री महोदय से कहूंगी कि आपके जो एवार्ड पड़े हुए हैं उनको निकालिए, फैसला करिए। जहां जहां पानी देना है वहां दीजिए। सारे राज्य हिन्दुस्तान के अंग हैं। यह हो सकता है कि कहीं पर अच्छी जमीन हो लेकिन आप उनको वक्त पर पानी नहीं दे पाए जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसी की एक मिसाल अपने राजस्थान कैनाल को देना चाहती हूं। यह कैनाल आज 8 साल पहले खत्म हो जानी चाहिए थी लेकिन पूरे रिसोर्सेज न भेजने के कारण अभी तक उसका पहला चरण, फर्स्ट स्टेज भी पूरी नहीं हो पाई है। आज अगर राजस्थान में कैनाल को पूरा कर लिया जाता तो राजस्थान में जो स्थिति आज है वह न होती। आज वहां अकाल होने के कारण हर साल 30 लाख पशु जो एरिड हैं वे यहां से माइग्रेट होकर

[श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूडावत]

चले जाते हैं । यह आपके आंकड़े बताते हैं । लाखों पशुधन हर साल आने-जाने में भूख से मर जाते हैं । यह अन्दाजा लगाया गया कि इस पशुधन के मरने से हमारा राष्ट्रीय नुकसान बड़ा जबर्दस्त हो रहा है ।

अगर आप चाहते हैं कि हमारी इकनोमी में सुधार हो और हमारे देश की फूड प्राबलम हल हो तो यह बहुत आवश्यक है कि हमारे देश में जो एरिड एरिया है, जैसे कच्छ, बाड़मेर, जेसलमेर और बीकानेर आदि का क्षेत्र है और जो बहुत लम्बा चौड़ा एरिया है वहां पर एग्रो-इंडस्ट्रियल आधार पर कुछ काम किया जाना चाहिए । वहां पर जो पशुधन है, शीपें हैं, उनकी चमड़ी, हड्डी और जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, उसका उपयोग किया जाना चाहिए । इसके अलावा जानवरों के सींगों और खुरों के उपयोग के लिए भी कारखाने लगाए जा सकते हैं । वहां पर फोडर की एक बड़ी समस्या बनी रहती है । मैं समझती हूं कि इस क्षेत्र को एक बड़े चरागाह में भी बदला जा सकता है । बरसात के अन्दर जब वहां पर थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है तो घास उग आती है । इसलिए उस घास को काटकर फोडर बैंक कायम किया जा सकता है । अगर इस प्रकार से योजनाबद्ध रूप से काम किया जाय तो कोई कारण नहीं है कि हम इस सूखे और अकाल की स्थिति से न निपट पाएं ।

मैं यह मानती हूं कि हमारे देश में अन्न की कमी है । सरकारी आंकड़े जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे देश में सिर्फ 2 प्रतिशत अन्न की कमी है । ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उठता है कि इस दो प्रतिशत की कमी को हम अपने देश में अन्न की बरबादी को बचाकर क्या पूरा नहीं कर सकते हैं ? निश्चय ही हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं । यह भी कहा जाता है कि हमारे देश में बहुत सा अन्न तो चूहे ही खा जाते हैं । जो अन्न हम विदेश से मंगाते हैं और उस पर जो पैसा खर्च करते हैं उसको अगर देश में ही अन्न की पैदावार बढ़ाने और चूहों आदि से अन्न की बरबादी रोकने में लगा दें तो हम इस दो प्रतिशत की कमी को पूरा कर सकते हैं । चूंकि केवल दो प्रतिशत अन्न की कमी है, लेकिन फिर भी विदेशी मुल्कों के अन्दर हिन्दुस्तान को बदनाम किया जाता है ।

आज हमारे विरोधी दल के लोगों के हाथों में भी एक हथियार आ गया है और वे इस देश को बदनाम करते रहते हैं कि इस देश में लोग भूखों मर रहे हैं । हमारे देश को जिस तरह से आज विदेशों में बदनाम कर रखा है उससे बहुत बुरा लगता है । मेरी लड़की यू. के. में है और वहां से पत्र लिखती रहती है कि यहां के अखबारों में हिन्दुस्तान की बहुत बुरी हालत बताई जाती है । ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान में लोगों को खाने को अन्न नहीं मिलता है । उसके पत्रों से मुझे ऐसा नजर आता है कि उसके दिमाग में एक तस्वीर बन गई है कि शायद उसकी मां को भी हिन्दुस्तान में दोनों वक्त का खाना मिलता भी है या नहीं । इस प्रकार का प्रचार वहां पर पत्रों में हो रहा है । आपने इस वक्त जो डिहोर्डिंग का अभियान चला रखा है, इसको आप चलाए रखें मैं समझती हूं कि अगर आप डिहोर्डिंग अच्छी प्रकार से पूरी सख्ती से करेंगे तो हम बहुत कुछ अन्न की दिक्कत को दूर करने में सफल हो सकते हैं । मुझे इस बात की खुशी है कि डिहोर्डिंग करने के लिए हमारे फूड मिनिस्टर ने कदम उठाए हैं । इस संबंध में उन्होंने जिस तरह से राज्य सरकारों को चेतावनी दी है, उसका एक असर पड़ा है और अन्न की वसूली हो रही है । अब राज्यों के चीफ मिनिस्टर भी इस बात को महसूस करने लगे हैं कि बार-बार केन्द्रीय सरकार से अन्न की मांग करने के बजाए खुद ही अन्न की वसूली की जाए तो ज्यादा अच्छा है । मैं इस बात को भी मानती हूं कि अन्न को बाहर निकालने के लिए जितनी पूरी चेष्टा की जानी चाहिए उतनी नहीं की गई है इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस दिशा में हम सख्त कदम उठाएं ।

अन्न की समस्या पर यहां पर हर साल बहस होती है, लेकिन फिर भी यह समस्या हल नहीं

होती है । आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे एरिगेशन हैं या अन्य साधन हैं, उनका पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए । यह वैज्ञानिक युग है । उत्तर प्रदेश में जो हंगरी के पम्प लगाए गए हैं वे 10 मील तक पानी को फेंकते हैं । अगर इसी प्रकार की योजना बनाई जाए तो कोई कारण नहीं है कि हम देश की अन्न की समस्या को हल नहीं कर सकते हैं । इस प्रकार की योजनाओं से काफी दूरी तक पानी पहुंचाया जा सकता है । मंत्री महोदय ने यह भी बताया है कि सर्वे करने से यह पता लगा है कि राजस्थान के अन्दर अन्डरग्राउन्ड वाटर काफी मात्रा में मिला है । बहुत खुशी की बात है लेकिन अंडरग्राउन्ड वाटर को हम बाहर निकाल दें, उस को टैप कर के उसको यूटिलिटी के काम में लाएं तभी कुछ होगा । इस समय हमारी सरकार की पालिसी इस ओर हो रही है कि हम चहुंमुखी, सर्वतोन्मुखी, प्रगति कर लें, और ठीक भी है, लेकिन इसका नतीजा यह निकला कि किसी एक लाइन में हम तरक्की नहीं कर पाए । मैं स्पष्ट रूप से, जोर देकर कहती हूं, इधर-उधर की तरक्कियां, इधर-उधर के खर्चे सारे रोक दिए जाएं और देश के सामने जो अहम प्रश्न हैं, सबसे बड़ा प्रश्न है फूड का और उसमें प्रोडक्शन कम होने से कीमतें ऊंची हुई हैं, इस परिस्थिति का पूरी ताकत के साथ, सारी शक्ति उसमें लगा कर मुकाबला किया जाए और राजनैतिक तौर पर भी इसका मुकाबला किया जाए । राजनैतिक तौर पर हमारी पार्टी जनता को साथ लेकर, उसका सहयोग लेकर और जो जनता इसमें सहयोग करना चाहती है उनको अपने साथ लेकर ऐसी जांच समितियां बनायी जाएं कि जिन लोगों ने सामान इकट्ठा कर रखा है, उन के सामान को डीहोर्ड करा सकें । आज जानबूझ कर प्रोडक्शन गिराया जा रहा है नफा कमाने के लिए । उस पर अनुशासन लाया जाए । हमारे सामने यह दिक्कतें हैं कि घेराव होते हैं, सभायें होती हैं, और ये कुरुक्षेत्र के मैदान रोजाना बनते हैं । सबसे जड़ की चीज यह है कि लोगों को खाने को मिले और सस्ती कीमत पर मिले—ठीक भाव पर भी मिले और ठीक मात्रा में पहुंच जाए । इसलिए मैं चाहती हूं की जो सर्वतोन्मुखी या चहुंमुखी प्रगति की जो बात है उसे साल दो साल के लिए बंद कर दिया जाए और केवल एक प्रगति में अपनी सारी शक्ति लगा दें और वह है रोजी, रोटी, कपड़ा और जरूरत की सारी चीजें जनता को आसानी से मिल जाए ।

श्री जगवीर सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं राजस्थान की सदस्या जो अभी बोल रही थीं उनको बधाई देना चाहता हूं और चाहता हूं कि यह सरकार यह वचन दे कि जितनी बातें उन्होंने कही हैं उनको पूरा कर देंगी तो मुझे कुछ कहने को बाकी नहीं रह जाता ।

यह जो बहस आज है भुखमरी पर, स्टारवेशन डेथ्स पर, फैमीन पर, इस संबंध में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि आज यह निर्विवाद सत्य है कि हमारे देश में कुछ अंचलों में भुखमरी है । यह भी निर्विवाद सत्य है कि हमारे यहां फैमीन कंडीशंस हैं । यह भी निर्विवाद सत्य है उपसभाध्यक्ष महोदय, कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ईस्टर्न यूपी. और असम में स्टार्वेशन से डेथस हुई हैं । मंत्री महोदय मानें या न मानें यह तो उनकी मर्जी है लेकिन सच्चाई पर परदा डालना कोई आसान बात नहीं है और न छिपाई जा सकती है । मुझे एक बात याद आ गई । मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना चाहता कि वेस्ट बंगाल में कितनी मौतें हुई हैं, कितनी असम में हुई हैं, कितनी ईस्ट बंगाल में हुई हैं, केवल दो तीन बातें कहना चाहता हूं कि आल पार्टी डेलीगेशन जो गया था उसके अनुसार 25,000 मौतें बतायी जाती हैं । मैं केवल दो-तीन आदमियों ने जो इस संबंध में कहा है उसके बारे में कहूंगा । वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने कहा है :

"People are living on grass roots".

यह हालत है कि ग्रास रूट्स पर वेस्ट बंगाल का आदमी रहता है । क्या इन्सान होकर घास खाएगा, यह एक सोचने का विषय है सरकार के लिए । उपसभाध्यक्ष महोदय, नूरूल इसलाम

[श्री जगवीर सिंह]

साहब जो कि जेनरल सेक्रेटरी हैं वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उन्होंने कहा है :

"Starvation deaths had been reported to the Committee from different parts of the State".

मैं नहीं जानता कि आपका कांग्रेस का जेनरल सेक्रेटरी असत्य बात कहता है। मैं यह भी नहीं जानता कि वहां का गवर्नर असत्य बात कहता है। महोदय, इतना ही नहीं, वहां के एक मंत्री महोदय संतोष रे ने कहा है :

"Fifteen million people in the rural areas of West Bengal are either starving or living on one meal a day".

वेस्ट बंगाल की सरकार का मंत्री इस बात को कहे और उसके बाद भी हमको शरम लगती हो इस बात के मानने में कि वेस्ट बंगाल के अंदर भुखमरी से मौतें हुई हैं, मैं नहीं समझता कौन सा परदा सरकार के सामने है कि इस बात को स्वीकार करें। हम को सत्य स्वीकार करना ही चाहिये। एक कहावत है "चोर की दाड़ी में तिनका"। कुछ लोग बैठे हुए थे। किसी ने कहा जो कि चोर है उसकी दाडी में तिनका है। जो असल में चोर था वह अपनी दाड़ी में हाथ लगाने लगा कि कहीं कोई तिनका तो नहीं है। वही हालत आज हमारी सरकार की है। हमारे श्री जगजीवन राम जी, जिनके पास फूड का महकमा है, उन्होंने रोम में कहा था :

He had no figures of hunger problem in India but he did not think that the people have starved to death.

इस तरह की बात को कहने की उन्हें क्या आवश्यकता थी ? उन्होंने यह भी कहा :

They do not get good quantity of nutrition.

इन बातों से यदि सारांश निकाला जाए तो यह निकलता है कि हमारे देश में स्टारवेशन से डैथ हुई हैं। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो स्टेटमेन्ट दिया है उसमें कभी भी यह बात स्वीकार नहीं की है कि देश में स्टारवेशन से डैथ हुई है बल्कि इन्होंने यह कहा है कि हमारे देश में फैमिन कंडिशन्स हैं। मुझे उनका एक बयान याद आता है जो उन्होंने अपने पिछले जन्म दिन के अवसर पर एक विदेशी सम्वाददाता को दिया था। उन्होंने यह कहा था :

There are people who used to pick grain from the dung. Now they get at least one meal a day. That is enough.

जिस देश के प्रधान मंत्री के सोचने का यह तरीका है कि पहिले हमारे देश के लोग गोबर में से दाना उठाकर खाते थे और अब तो उनको एक वक्त खाना पड़ता है जो कि काफी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से और विशेष कर मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस ढंग से सोचने वाला प्रधान मंत्री क्या देश की अनाज की समस्या को हल कर सकता है जब कि हमारे देश में बंगाल, उड़ीसा और आसाम में स्टारवेशन से लोगों की मौतें हो रही हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें, प्रधान मंत्री विचार करें, सरकार विचार करे कि इस समस्या को हल करने के लिए किस तरह से कार्य किया जाना चाहिये। इतना ही नहीं अगर आज हमें हालत की तुलना करनी है तो 1943 के फैमिन के बाद पहिली बार हमारे देश में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जो ये मौतें हुई हैं हमारे देश के अन्दर, उनमें कौन लोग मरे ? क्या हमारे चौधरी रणवीर सिंह जी का वजन कम हो गया ? नहीं। क्या मंत्री जी को तकलीफ हुई है ? नहीं। तकलीफ हुई है गरीब आदमी को। माल न्यूट्रेशन की बात कही जाती है और इस बारे में बहुत से अखबारों का हवाला दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं भी इस सम्बन्ध में दो अखबारों का उल्लेख दे सकता हूं। चंडीगढ़ से ट्रिब्यून ने कहा है :

"The average Indian's share of food had been worked out to 2100 calories and 52 grains of protein every day against the minimum requirement of 2357 calories and 44.5 grams of protein an official spokesman said on 21-10-73".

इतना ही नहीं हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड ने कहा है :

The calories content of Indian diet is the lowest in the world—only 1,81. calories a day.

ठीक है, माल न्यूट्रेशन की बात हमने मान ली और मंत्री जी कहते हैं कि हमारे यहां स्टारवेशन से डैथ नहीं हुई है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि माल न्यूट्रेशन से जो डैथ हुई हैं क्या उसको स्टारवेशन डैथ नहीं माना जायेगा ? अगर एक आदमी को कई दिनों से माल न्यूट्रेशन नहीं मिलेगा, उसे कम भोजन मिलता है और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसको स्टारवेशन से डैथ नहीं माना जायेगा ? हमारे मंत्री जी कह दें कि हम पूरा अनाज नहीं दे सकते हैं, पूरी खुराक नहीं दे सकते हैं, तो फिर इसके अन्दर इतनी परेशानी क्यों है और इसमें आपत्ति क्या है और न इससे कोई पहाड़ ही टूटने वाला है।

It is a fact which cannot be denied with lame excess.

मरा कौन है ? शहर में रहने वाला नहीं मरा है। एक मित्र कह रहे थे कि रिनेसां पर भीड़ क्यों है। रिनेसां पर भीड़ होगी दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई के अन्दर। ग्राम के अन्दर जो व्यक्ति रहता है उसका पैसा फिल्म देखने पर खर्च नहीं होता। मेरी पहले भी शिकायत थी और आज भी शिकायत है कि सरकार के दृष्टिकोण में अन्तर है गांव और शहर में रहने वालों के बीच। अन्न की कमी से गांव में रहने वाला व्यक्ति मरा है, गरीब आदमी मरा है। मालदार आदमी जो पिक्चर देखने जाता है वह स्टारवेशन से नहीं मरा है।

हमारे देश के अन्दर गरीबी क्यों है ? 1971 में नारा दिया गया 'गरीबी हटाओ' गरीबी हटाओ का नारा देने के बाद आज कहते हैं कि परचेजिंग कपैसिटी नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मैं आप के माध्यम से जानना चाहता हूं, अधिष्ठाता महोदय, कि इसके लिए वह सरकार जिम्मेदार है या नहीं जो 27 साल से बराबर कुर्सी में चली आ रही है और आज कहती है कि हमारे देश में लोगों के पास पैसा नहीं है। दोनों में कन्ट्रेडिक्शन है। क्या इस देश के अन्दर गल्ला कम है या परचेजिंग कपैसिटी कम है ? क्या हम गल्ला सबको खाने के लिए पूरा दे सकते हैं ? अगर दे सकते हैं तो उसके बाद सवाल आता है कि परचेजिंग कपैसिटी है या नहीं है। ये दोनों सैल्फ-कन्ट्रेडिक्टरी बातें हैं।

गरीबी हटाओ का नारा इन्दिरा जी ने बाद में दिया हो, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार का बराबर प्रयत्न रहा होगा कि देश से गरीबी दूर हो, कभी सरकार का यह प्रयत्न नहीं रहा होगा कि इस देश के अन्दर गरीबी बढ़े। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि फिर भी ऐसे व्यक्ति जो बिलो पावर्टी लाइन कहे जा सकते हैं जिनकी आमदनी 20 रुपये प्रति माह भी नहीं थी 60-61 की प्राइसेज के हिसाब से उनकी तादाद देश की कुल आबादी की 2/3 थी '67 में आज वह 72-73 में 2/3 हो गई है जबकि बिड़ला और टाटा की सम्पत्तियां कई गुना बढ़ गई हैं। इस देश के अन्दर अगर इसी प्रकार गरीबी हटती रही तो वह दिन दूर नहीं जबकि सब सम्पत्ति टाटा और बिड़ला, और 75 परिवारों के हाथ में पहुंच जायेगी, जो इस देश में राज करेंगे।

अधिष्ठाता महोदय, इस बहस में हमको देखना यह पड़ेगा कि आखिर कारण क्या है जिनकी वजह से आज देश के अन्दर यह स्थिति उत्पन्न हुई है। मैं बहुत सफाई से कहना चाहता हूं कि इस स्थिति के उत्पन्न होने का कारण केवल एक है कि हमने महात्मा गांधी के सिद्धान्तों को छोड़कर और सिद्धान्त अपनाए हैं। महात्मा गांधी ने हमेशा यह कहा था :

Agriculture first, small-scale industries second and heavy industries afterwards.

लेकिन '55 में आवडी के रोशन के बाद नेहरू जी के आग्रह पर प्रायोरिटीज बदली गईं। पहले प्लान में कृषि के ऊपर 37 प्रतिशत एक्सपेंडीचर हुआ था, जिसको घटाकर दूसरे प्लान में 21 प्रतिशत कर दिया गया और करीब वही 21 प्रतिशत आज तक चला आता है—थोड़ा बहुत डीविएशन

[श्री जगवीर सिंह]

हो सकता है, लेकिन करीब करीब वही। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा था कि सबसे बड़ा कारण यह है कि कृषि को जितना ध्यान देना चाहिए था उतना नहीं दिया गया। यह सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश के अन्दर आज यह स्थिति उत्पन्न हुई।

इतना ही नहीं, मैंने पहले शायद कहा हो या नहीं, मैं एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं कि मेरा आज भी विश्वास है कि देहात के अन्दर हिन्दुस्तान रहता है। महात्मा गांधी ने कहा था :

"India lives in the villages".

आज जो असली हिन्दुस्तान है वह देहात के अन्दर है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ते के अन्दर नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि इस बीच में जो हमारी पालिसी रही है क्या उस पालिसी से गांव और शहर की विषमता को हमने बढ़ाया है। जो गरीब पहले ही गरीब था क्या उसकी गरीबी और बढ़ी है और मालदार की मालदारी बढ़ी है या नहीं। अधिष्ठाता महोदय, प्रोफेसर-शिनी इकानामिस्ट हैं। उन्होंने कुछ आंकड़े दिये हैं, मैं उनको आपके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है—

पहली प्लान के आखीर में गांव और शहर की आमदनी का अन्तर—गांव वालों की आमदनी कुल आमदनी की 27 प्रतिशत थी जब कि वह घटकर दूसरे प्लान के अन्त में केवल 24 प्रतिशत रह गई और तीसरी प्लान के अन्त में 20 प्रतिशत और 1966-67 में 18 प्रतिशत। उसके बाद के 3 साल के आंकड़े मौजूद नहीं हैं, हों भी तो वह मुझे उपलब्ध नहीं हो पाये। तो मैं यह कह रहा था कि हमारी सरकार की मौलिक नीति जो है वह इस प्रकार की है जिसने इस स्थिति को उत्पन्न कर दिया।

अब सरकार को चाहिए कि सरकार बहुत बहादुरी के साथ इस स्थिति का सामना करे। आज कहा जाता है कि बाबू जगजीवन राम जी के हाथ में यह विभाग आया है, वह जिस महकमे में गये हैं उसमें उनको पूरी सफलता मिली है, मैं चाहता हूं कि ईश्वर करे यहां भी उनको सफलता मिले ताकि यह देश बच सके, न केवल मजदूर बच सके, यहां का गरीब आदमी बच सके, यहां का गांव वाला बच सके, यहां के बहनों के इज्जत बच सके जिन्होंने बच्चों को बेचकर रोटियां खाई हैं।

(Time Bell rings)

मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। गवर्नमेंट की तरफ से कई बातें कही गई हैं। लेकिन हमें देखना होगा कि आखिर इन 27 वर्षों के अन्दर कितना ज्यादा अनाज पैदा हुआ, कितनी ज्यादा जमीन को हम खेती के अन्दर ला पाये हैं, कितनी ज्यादा जमीन पर हम खेती कर सके हैं, क्या हमने किसानों को इंसेंटिव दिये हैं अनाज पैदा करने के लिए यह सवाल है जिन पर विचार करना होगा।

अधिष्ठाता महोदय, आज इस स्थिति का हल केवल इनकीज्ड प्रोडक्शन हो सकता है। यह नहीं हो सकता है कि हम विदेशों में जाकर भीख मांगें। बाबू जगजीवन राम ने जो कहा कि मैंने तो गैम में टेक्नालाजी देने की बात का जिक्र करते समय अपने देश का नाम लिया। प्रधान मंत्री जब कनाडा में गईं तो वहां पर टेलीविजन में दिखलाया गया, यहां के आदमियों को, भूखे मरते हुए। हमारे देश की इज्जत विदेशों में घटी या नहीं? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी अगर आप इस देश को बचाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यहां का आदमी खुशहाल हो, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप पैदावार बढ़ाकर इस देश की हालत सुधार सकते हैं। आप दूसरे देशों से अनाज मंगाकर सुधार सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास नहीं है।

अधिष्ठाता महोदय, आज ही एक इकानामिस्ट की एक किताब मुझे मिल गई। उन्होंने कहा है—

> "The need for increased fertilisers has been so obvious that I simply cannot understand the failure to provide them in sufficient quantities".

लेकिन आज हालत क्या है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं क्योंकि मैं भी गांव से आता हूं कि आज किसान तैयार नहीं

हैं आपकी बढ़ी हुई कीमतों पर खाद खरीदने के लिए। आज किसान सोचता है इस बात को। आपने नहीं कहा है कि आप कीमतों में कितनी वृद्धि करेंगे अगले साल में। अगर आपने बतला दिया होता किसान को कि हम इतना पैसा देंगे अगली फसल के लिए तुम खूब पैदा करो तो इस देश में वे भूखे नहीं मरने देते। अगर विश्वास किसान को दिया होता तो किसान आपको सहयोग देते। यह देश खुशहाल हो सकता है लेकिन इसके लिए आपको इनिशिएटिव लेना होगा। किसान से आपको द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। आज समझा जाता है कि किसान मालदार है। आज डी-होर्डिंग की बात भी की जाती है। मैं मानता हूं कि किसानों के पास गेहूं हो सकता है तो वह बड़े किसानों के पास हो सकता है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही था? हमारी सरकार ने गांव में रहने वाले भूमिहीन के प्रति कोई इन्तजाम किया था? मेरा कहना है आपने उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं समझी। अगर आप जिम्मेदारी समझते हैं तो रणबीर सिंह जी के प्रति समझते हैं जिनके पास बहुत गेहूं हो सकता है लेकिन गरीब मजदूर के प्रति नहीं।

इन शब्दों के साथ आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार से कि इन सब बातों का, इन सब समस्याओं का हल इन्क्रीज्ड प्रोडक्शन है। उसके लिए आप को किसान को इनिशिएटिव देना होगा, उसे विश्वास में लेना होगा। उसको फेयर प्राइस देनी होगी वरन् इस देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा): सभापति जी, आज चर्चा हो रही है देश में कम पैदावार की वजह से जो देश में मुश्किलात आई हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : आप अपना गेहूं निकालें।

श्री रणबीर सिंह : मान्यवर, अभी हमारे पूर्व वक्ता ने जिक्र किया गेहूं के बारे में वे इस बात को भूल गए कि जब देश आजाद हुआ था और जिस सूबे के हम रहने वाले थे उस सूबे के अन्दर इतना अनाज पैदा नहीं होता था जितना वहां के आदमियों को खाने की जरूरत थी। उस सूबे के अन्दर 35-40 लाख आदमी बेघर हो कर आये थे और आज सारे देश की नजर अनाज के लिए हरियाणा और पंजाब प्रदेश की तरफ जाती है, हरियाणा प्रदेश जिसका जन्म 1966 में हुआ था इसमें 1966 से इतना अनाज पैदा नहीं होता था जितना हम को जरूरत होती थी लेकिन मुझे खुशी है कि आज देश की मुश्किलात में हमारा प्रदेश और पंजाब प्रदेश जिसके हम पहलेवासी थे की तरफ अनाज के लिये देखते हैं आज वहां बहस नहीं की जाती है। जो आदमी बोलते बहुत हैं, बहस बहुत करते हैं वे काम कम करते हैं और यही आज देश की सबसे बड़ी मुश्किल है।

हमारे देश के अन्दर जमीन के नीचे अगर कहीं मीठा पानी है तो वह उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, बंगाल में है, असम में है। इस देश को ज्यादा योजनाओं की आवश्यकता नहीं है। इस देश के अन्दर अगर उत्तर प्रदेश के मीठे पानी को बिहार के जमीन के नीचे पड़े मीठे पानी को, असम और बंगाल के जमीन के मीठे पानी को बाहर निकाल कर प्रयोग में लाया जाए तो मैं मानता हूं कि इस देश के अन्दर अनाज की कमी नहीं रहेगी। सभापति जी, मैं आपको बताता हूं कि हमारे दरियाओं के पानी का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास था पानी का और जमीन के नीचे मीठा पानी नहीं था खारा पानी था लेकिन हौसले से हमारे प्रदेश ने काम किया वहां के काश्तकारों ने काम किया, वहां की सरकार ने काम किया और तेजी से काम किया। खुद खड़े हुए और देश की मदद के लिए आगे आए।

जिस बात का जिक्र अभी हमारे पूर्व वक्ता ने किया इससे पहले कि मैं उस बात की तरफ जाऊं मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि देश की तरक्की की निशानी अगर देखनी है तो चौधरी जगवीर सिंह में देखी जा सकती है। वह भी एक किसान हैं। हिन्दुस्तान के

[श्री रणबीर सिंह]

अन्दर 25-27 साल पहले किसान के मायने होते थे कि न उसके पास कपड़े होते थे और न जूते होते थे। और अगर उसको बाहर जाना होता था तो वह दूसरे लोगों के पास चीजें मांगने के लिए जाता था। चौधरी जगवीर सिंह जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले यह स्थिति थी कि जब गांव के किसी भाई को बारात में जाना होता था या बाहर कहीं जाना होता था वह किसी से चादर मांगता था, किसी से दूसरी चीजें मांगता था। आज यह हालत नहीं है। जमाना बदल गया है। चौधरी जगवीर सिंह बता सकते हैं कि उनके गांव में कितने ट्रैक्टर हैं और कितने बिजली के पम्प चलते हैं।

3p.m.

श्री जगवीर सिंह : पम्पों को कितने घंटे बिजली मिलती है?

श्री रणवीर सिंह : हमारी सरकार ने गांवों में खेती के सुधार के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। इस बात को देखने से पता चलता है कि हमारे देश के गांवों में पहले कितनी खेती होती थी और आज कितनी होती है? हमारे विरोधी दल भाइयों में और हम में फर्क इतना है कि हम इस तबदीली को कबूल करते हैं लेकिन हमारे विरोधी भाई इसको कबूल नहीं करते हैं। आज हमारे देश में मुश्किल यह है कि जो भाई काम नहीं करते हैं वे सबसे बड़े नेता हैं और जो आदमी या प्रदेश काम करते हैं वे पीछे की पंक्ति में रहते हैं।

श्री महावीर त्यागी (उत्तर प्रदेश) : एक बात मुझे यह कहनी है कि आज हालत यह है कि आज जो गवर्नमेन्ट बनती है उसमें किसानों के नुमायन्दे बहुत कम हैं। आज शहरों के लोग ही, जिनमें वकील आदि होते हैं, कैबिनेट बनाते हैं। इसलिए गांवों की परवाह पूरी तरह नहीं होती है।

[The Vice-Chairamn (Shri Jagdish Prasad Mathur) in the Chair]

श्री रणवीर सिंह : त्यागी जी कह रहे हैं कि आज जो सरकार बनती है वह शहरों के लोग ही बनाते हैं। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पहले त्यागी जी भी कुछ बने थे और वे हिन्दुस्तान के फाइनेन्स कमीशन के चेयरमैन थे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि त्यागी जी के बाद श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी दूसरे वित्त आयोग के चेयरमैन बने थे और उस वित्त आयोग ने जो सिफारिश की थी वे सिफारिशें त्यागी जी वाले वित्त आयोग की सिफारिशों से गांव वालों के और प्रदेशों के हित में ज्यादा थीं मुझे यह मालूम नहीं कि उस वक्त त्यागी जी पर शहरों के लोग चढ़े हुए थे या यहां के पढ़े-लिखे लोग चढ़े हुए थे। अब जब वे वहां से निकले तो उनको शहर वाले दिखाई देने लगे।

उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर प्रधान मंत्री जी का भी जिक्र करना चाहता हूं। सन् 1966 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधान मंत्री बनी थीं तो उस वक्त बिजली से चलने वाले पम्पों की तादाद इस देश में 10 लाख से भी कम थी और आज उनकी तादाद 25 लाख से भी ऊपर है।

श्री जगवीर सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि ये पम्प कितने घंटे चलते हैं?

श्री रणवीर सिंह : चौधरी साहब पूछ रहे हैं कि ये पम्प कितने घंटे चलते हैं। पहले तो इन्हें बिजली मिलती ही नहीं थी, आज ये पूछते हैं कि पम्प कितने घंटे चलते हैं। अगर हमारे ये माननीय सदस्य देहातों में जाकर बिजली की स्थिति को देखें तो मैं यह समझता हूं कि इन लोगों को श्रीमती इंदिरा गांधी के गीत गाने चाहिएं जिन्होंने इस देश के गांवों में बिजली पहुंचा दी है। पहले हमारे देश के 75 हजार गांवों में बिजली पहुंच चुकी थी, आज हिन्दुस्तान के डेढ़ लाख गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। मैं यह मानता हूं कि इस देश के हर गांव में बिजली जानी चाहिए और किसानों को बिजली मिलनी चाहिए। कारखाने में रात को भी काम हो सकता है, खेत में तो बिजली दिन में मिलनी चाहिए . . .

श्री जगवीर सिंह : इतना ही मनवा दीजिए बस।

श्री रणवीर सिंह : बात तो दुरूस्त है। अगर मानने से बात चलती हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूं बहिन इंदिरा गांधी आपसे पहले हां कर जाएंगी . . .

SHRI G. LAKSHMANAN (Tamil Nadu): It is a State subject. How can the Prime Minister take credit for it?

श्री रणवीर सिंह : लक्ष्मणन जी, आप भूल जाते हैं आपके प्रदेश के अंदर जो तरक्की हुई है किसलिए हुई है, मेरे प्रदेश के अंदर जितनी तरक्की हुई वह किसलिए हुई है ? वह डी.एम.के. की सरकार की बिना से नहीं हुई है, हमारी सरकार के बिना से नहीं हुई है, वह हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकार ने रुपए की सहायता दी है। आपको इस लायक किया है कि आप खड़े हुए, आपको कर्जा दिया ताकि आप कूएं लगा सकें, आप माइनर इरिगेशन का काम बढ़ा सकें और बिजली लगा सकें।

SHRI G. LAKSHMANAN : Can he say how much financial assistance has been given to the Sate Government for getting pump sets?

श्री रणवीर सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, इसका जवाब स्पेसिफिकली आप देंगे। अगर मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा।

SHRI G. LAKSHMANAN : Can he give the information ?

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : चौधरी साहब आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री रणवीर सिंह : आपने जिक्र किया था और मैं समझता हूं उनको ऐतराज भी हुआ। बात महत्वपूर्ण है कि जो प्रदेशों की हमारी योजनाएं हैं उनके अंदर भारत की सरकार कितनी वित्तीय सहायता देती है, रुपए की कितनी सहायता देती है ? क्या आप इस बात को मानते हैं कि वित्त की सहायता के बगैर आपकी डी.एम.के. पार्टी की सरकार आगे बढ़ रही है या हमारा प्रदेश और पंजाब का प्रदेश आज आगे बढ़ा है ? लेकिन मैं यह जानता हूं कि हमारे प्रदेश की सरकार को भाखड़ा डैम की योजना के लिए पैसा मिला और इसीलिए आज हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों को हम अनाज दे सकते हैं, दूसरे प्रदेशों के लिए कभी कभी बिजली भी थोड़ी बहुत दे सकते हैं। हमारे यहां भी बिजली का खर्च ज्यादा बढ़ा तो डी.एम.के. का यह ख्याल मात्र है क्योंकि मैं जानता हूं मद्रास में एक वक्त था जब मद्रास दो प्रदेश में बांटे थे मद्रास में उनकी पार्टी बनी थी और आन्ध्र वाले भाई माफ करेंगे वे कहा करते थे कि मद्रास भूखा मर जाएगा अगर वह हमारे साथ नहीं आएगा। तब डी. एम. के. के नहीं श्री कामराज मुख्य मंत्री थे। उन्होंने अपने मुख्य मंत्री पद के दौरान मद्रास जो एक डैफिसिट स्टेट था उसको एक सर्पलस स्टेट बनाया और आपने तो यही सेवा की थी . . .

SHRI G. LAKSHMANAN : For your information, Shri Kamaraj was not there. Shri Rajagopalachari was there.

श्री रणवीर सिंह : थोड़े समय के बाद ही कामराज जी मुख्यमंत्री बनाये गये थे जिन्होंने तामिलनाडु का नक्शा बदला था. . . कि उनको एक बच्चे से हरवा दिया। खैर, वह वक्त की बात होती है, कभी आपके साथ भी ऐसा बनेगा, वह वक्त भी आएगा जब आपको देखना पड़ेगा कि आपका मुख्य मंत्री 18 या 19 वर्ष के बच्चे से हारेगा क्योंकि वह आने वाली नस्ल इस बात को भूल नहीं सकती है कि हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। (व्यवधान) चौधरी साहब, जाने दो क्यों कहलवाते हो मुझे बुड्ढे के खिलाफ मेरे दिल में उनके लिए आदर है। मुजफ्फरनगर के चुनाव में कौन हारा था कौन जीता था, 1971 के चुनाव के वक्त ? आप इस बात को भी भूल जाइए आप कितने जीते। उसको जाने दीजिए, वह कहानी निराली है।

SHRI G. LAKSHMANAN : Prime Minister Indira Gandhi can also be defeated.

श्री रणवीर सिंह : मैं मानता हूं कि हमारे देश के लिए यह कोई इज्जत की बात नहीं है कि हम विदेशों से अनाज मंगायें जब कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, हम बाहर

[श्री रणबीर सिंह]

रों अनाज मंगायें, कपास मंगायें और बाहर से कोई और चीज मंगायें जिस चीज को हम अपने खेतों में पैदा कर सकते हैं। हमें अपने देश को हर चीज के लिए स्वावलम्बी बनाना चाहिए और इस बात में दो रायें नहीं हो सकती हैं। सरकार और विरोधी दल के जो सदस्य हैं वे सब चाहते हैं कि हम हर चीज में स्वावलम्बी बन जायें। लेकिन स्वावलम्बी बनने के लिए सरकार की नीति में कुछ फर्क आने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ प्रदेशों की सरकारों और लोगों के काम करने के तरीके में भी फर्क आना चाहिये। अगर आपको इस बात की शिक्षा लेनी है, तो मैं एक बात कहता हूं उन लोगों से जो प्रताप सिंह कैरों के क्रिटिक हैं, जो बंसीलाल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, कि वे लोग पंजाब और हरियाणा में जाकर देखें और वहां से शिक्षा लें। वहां पर किस तरह से तरक्की हुई है और 50 मील तक नहरें एक साल के अन्दर बन गई हैं। जब देश में तेजी आयेगी तब ही काम हो सकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश में कुछ तेजी आनी शुरू हो गई है और वह आगे बढ़ा है। लेकिन इस तेजी को तो हमारे कुछ लोग रोकने के लिए तैयारी में हैं क्योंकि वे घेराव में लगे हुए हैं। मैं मानता हूं जैसा कि उन्होंने जिक्र किया है कि घेराव की जरूरत है। अगर चौधरी रणबीर के पास या चौधरी जगबीर सिंह के पास उसकी जरूरत से ज्यादा अनाज है, अगर किसी मंत्री के पास और साहूकार के पास उसकी जरूरत से ज्यादा अनाज है, तो उसके घेराव की जरूरत है। लेकिन आज की हालत में असेम्बलियों के घेराव की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहां पर भी तो हमारे जैसे गरीब आदमी बैठते हैं। अगर आप और मेरे जैसे नहीं तो दूसरे गरीब होंगे। वहां पर भी तो गरीब आदमी बैठते हैं। तो ये लोग क्रान्ति के नाम से क्रान्ति की बात करते हैं, लेकिन, देश को क्रान्ति की तरफ ले जाते नहीं हैं।

जैसा त्यागी जी ने कहा, मैं इस बात को मानता हूं कि हमारी नीति में परिवर्तन होना चाहिये। मैं कल, परसों कपास के संबंध में बोल रहा था और उस वक्त मैंने कहा था कि क्रेडिट स्क्वीज का बहाना लेकर किसानों को परेशान किया जा रहा है और उनके माल को नहीं उठाया जा रहा है। आज देश की आर्थिक हालत खराब होने के नाम पर इस तरह की कार्यवाही की जा रही है। मैं नहीं मानता कि हमारी आर्थिक हालत खराब नहीं है, लेकिन इस बारे में हमें आपस में सोच विचार और सलाह मशवरा करना चाहिए। आप कहते हैं कि बाजार में चीजों के दाम बढ़ गये हैं और उसको कम करना चाहिए। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमको ऐसे खर्चों में कमी करनी चाहिये जिसके द्वारा देश में पैदावार नहीं बढ़ती है। जिन चीजों के द्वारा खेतों और कारखानों में पैदावार बढ़ती है, उन चीजों में कोई कमी नहीं करनी चाहिये और उन चीजों के लिए पैसों में रोक नहीं लगानी चाहिये। उस रोक के माने तो अपनी तरक्की पर रोक लगा देना होगा।

मैं यह बात समझ सकता हूं कि जो लोग स्मगलिंग का काम करते हैं, जिनके पास चोरी का धन है, उनके काले धन को पकड़ कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये और सरकार को उनको पकड़ना चाहिए। उन लोगों का घेराव करके इस बात के लिए मजबूर किया जाये कि वे काले धन को सरकार के सामने लायें ताकि वह रुपया देश की तरक्की के लिये लगाया जाये। तो इस तरह के रुपये को आप रोकें, लेकिन जो आपने क्रेडिट स्क्वीज की बात कही है, उससे तो कपास की पैदावार कम हो जायेगी, सरकार उसको नहीं खरीद सकती है, तो यह एक गलत नीति है। इसके माने तो यह हुए कि जो किसान मेहनत और पसीना बहाकर कपास पैदा करता है, उसकी खरीद एयर कंडिशन में बैठे हुए साहूकार करेंगे और उनके अधीन इन लोगों को छोड़ दिया जायेगा। इस तरह की जो नीति है वह एक गलत नीति है और क्रेडिट स्क्वीज के माने यह नहीं होने चाहियें कि गरीब किसान परेशानी में पड़ जायें। मैं यह मानता हूं कि जो रिजर्व बैंक के बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, जो बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, उनकी यह सोच हो सकती है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह के सोच में तबदीली की आवश्यकता है और उनके

दिमागों में देहात वालों की भलाई के बारे में सोच होनी चाहिये और वह सोच यही हो सकती है। देश के अंदर जो पैदावार के लिए पैसा लगता है उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए।

श्री महावीर त्यागी : 5-7 वर्ष से इस बात के लिए बराबर कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट विलेज-वाइज सर्वे करें प्लानिंग के लिए कि किस गांव में किस चीज की जरूरत है और उसकी बेसिस पर प्लान शुरु हो। यहां तो प्लानिंग रुपए के बंटवारे की होती है कि इतना रुपया इस पर खर्च कर दो। यह कोई सोचता नहीं कि किस काम पर खर्च होना है, किस गांव में क्या बनना है। मेरा कहना यह है कि अगर आप अपनी पार्टी को और गवर्नमेंट को इस बात के लिए तैयार कर दें कि वह गांव-गांव का सर्वे कराए कि कौन से गांव में क्या तरक्की हो सकती है और उसके हिसाब से प्लानिंग हो तो एक वर्ष के अंदर सारा किस्सा साफ हो सकता है।

श्री रणवीर सिंह : त्यागी जी, जो आपके उद्देश्य हैं उनसे मैं सहमत हूं लेकिन जो आप कहते हैं उससे तनख्वाहदारों की तादाद बढ़ेगी। यहां सर्वे की कोई कमी नहीं है। इस देश के अंदर सर्वे बहुत हो गया है, सर्वे को बन्द करो। इस बात को आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जाने दीजिए, हरियाणा को और पंजाब को, तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पानी मीठा है, जहां किसी इंजीनियर के जाने की जरूरत नहीं है, किसी तनख्वाहदार को तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है . . .

श्री महावीर त्यागी : मैं यही कह रहा हूं। सर्वे के मानी मेरे यह नहीं है कि इंजीनियर भेजे जायें सर्वे के मानी यह है कि गांव के प्रधान को चिट्ठी लिख दी जाये कि अपने-अपने गांव में बताओ कितनी जमीन है, कितनी आबपाशी है, स्कूल कैसा है, अस्पताल कितनी दूर है। उसकी लिखी हुई चिट्ठी के ऊपर प्लान बेस कर दीजिए।

श्री रणवीर सिंह : मैं आप जितना तजुरबेकार नहीं हूं, लेकिन एक बार आप मेरी भी मानेंगे कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और इस सदन के जो तजुरबेकार सदस्य हैं वे जानते हैं कि देश की जरूरत क्या है, गांव के सरपंच के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है जैसा चौधरी जगबीर सिंह ने कहा, कि आज हम फैसला करें कि जो खेती की तरक्की के लिए पैसा होगा वह और चीजों के मुकाबले में ज्यादा खर्च होगा। हम 25, 30 और 40 प्रतिशत खेती पर खर्च करने का फैसला करें तो इस क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं।

माननीय गौरे जी यहां नहीं हैं। पिछली दफा उनके प्रदेश में 150 करोड़ रुपया लगा उन्होंने कहा 150 करोड़ रुपया लगा तथा कभी फायदा हुआ। उसके ऊपर भी शक करेंगे। यही मुश्किल है। हमारे और आप जैसे विद्वान जो लोगों के नुमाइन्दे बन कर आते हैं उनके ध्यान में टीका-टिप्पणी करते वक्त यही रहता है कि उनको किसी चीफ मिनिस्टर से गिला है या किसी पार्टी में मिला है, वे यह नहीं सोचते कि जो हम कह रहे हैं उसका असर क्या होगा। मुझे इतना ही निवेदन करना है कि आज देश के अन्दर जरूरत इस बात की है, जैसी कि इन्दिरा गांधी जी ने शुरूआत की है, कि माइनर इरीगेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा रुपया दिया जाये। मैं तो यह कहता हूं कि कोई ज्यादा बड़े तंत्र की जरूरत नहीं है एक छोटा सा मंत्री इस देश को आगे बढ़ा सकता है। जो भी कोई योजना खेती में सिंचाई बढ़ाने के लिए या खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए एक साल में पूरी की जा सकता है उसके लिए खर्च के ऊपर कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिए।

श्री महावीर त्यागी : जरूर।

श्री रणवीर सिंह : उसके ऊपर किसी बहस की जरूरत नहीं, विशेषज्ञों की राय की ज्यादा जरूरत नहीं क्योंकि देश के लिए अनाज चाहिए।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : वही तो यह सरकार करना नहीं चाहती।

श्री रणबीर सिंह : यह सरकार तो करना चाहती है लेकिन आप लोग घेराव में लगे हुए हैं । आप अपनी हार की झेंप मिटाने के लिए किसी का पर्दा उठाये फिरते हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : उस तरफ नहीं, इस तरफ बोलिए ।

श्री रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष जी, मुझे उस तरफ भी बोलना पड़ता है और आपकी तरफ भी बोलना पड़ता है । मुझे याद है जब आप बोल रहे थे तो आपने क्या कहा था । मुझे इतना ही निवेदन करना है कि जैसे हरियाणा में हमने साबित कर दिया है कि एक साल की योजना एक साल के अन्दर ही खत्म हो सकती है । अगर हम 10 करोड़ रुपये की योजना आपके सामने, कृषि मंत्रालय के सामने भेजेंगे और एक साल की अवधि में उसको पूरा कर देंगे, 11 महीने में कर देंगे, 13वां महीना नहीं आने देंगे तो उसको आपको सहायता देनी चाहिए । जो इम्तिहान में पास हो, जिस काम में आपका विश्वास है कि यह काम साल में पूरा हो सकता है तो उस पैसे को कम-से-कम आप अवश्य दीजिए । चाहे कितना पैसा लगे अगर उस पैसे से अनाज की पैदावार बढ़ सकती है तो उसके ऊपर कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिए । इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके मंत्रालय में नहर का भी मंत्रालय आ गया, सिंचाई मंत्रालय भी है । . . . *Interruption* ओम मेहता जी आप कहां फंस गये, मैं पैसा मांगता हूं, आप बीच में आ गये ।

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : अगर इतनी आसानी से पैसा मिलता है तो मैं चला जाता हूं ।

उप-सभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : ओम मेहता जी से झगड़ा करने पर पैसा नहीं मिलेगा ।

श्री रणबीर सिंह : तो मैं निवेदन कर रहा था कि कृषि मंत्रालय के पास अब सिंचाई विभाग भी आ गया है । जवाहरलाल नेहरू प्रोजेक्ट हमारे प्रदेश के अन्दर एक योजना बनाई है और उस योजना के जरिये हम जमुना जी का वह पानी जिसको बहन चूड़ावत जी कह रहीं थीं कि दरिया में जाकर बहता है वह समुद्र में बह जाता है, उस बरसात के पानी को 400 फीट उठाकर सूखे वाले खेतों में डालना चाहते हैं और उस योजना को एक साल में हम पूरा करना चाहते हैं । तो आप 10-15-20 करोड़ रुपये जितना दे सकें उतनी आप हमें छूट दें । हमारी सरकार का यह भी हौसला है कि अगर साल के आखीर में दे सकें तो हमको विश्वास दिला दें तो हम अपने हौसले पर इस काम को चालू कर देंगे । हमको इस बात का जोर नहीं है कि हमको आज ही पैसा मिले जैसे राजस्थान के अन्दर पहले पैसा दो, फिर काम होगा । जो कुछ भी हो रहा हो, उनकी मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं जानता हूं कि कई प्रदेश हैं जिनके काम करने का मंहगा तरीका है, देर भी लगती है । जिन प्रदेशों के अन्दर काम करने की शक्ति है और जो प्रदेश आगे बढ़ सकते हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए । बहुत सारे भाई हैं जो मानते हैं कि कुछ इलाके बहुत पिछड़े रह जायें तो देश के अन्दर अच्छी योजना नहीं बनेंगी, उसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन साथ में सबसे बड़ा ख्याल यह होना चाहिये कि देश में अनाज पैदा होना चाहिए । कहां हो, किस कोने में हो, इस बात की हमें फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है । आज तो आवश्यकता यह है कि जैसी आपने परेशानी जाहिर की मैं नहीं मानता हूं कि आज हमारे देश में कोई भूख से मर रहा है । ये भी जिस तरह से कुछ भाई हैं जो घेराव खामखां करते हैं, यह भी एक नारेबाजी है । यह इस देश की इज्जत को ऊंचा नहीं करती, इस देश की इज्जत को गिराती है । मैं यह मानता हूं कि हमारे देश के अन्दर अगर कोई भूख से परेशान है, कोई तकलीफ में है तो उसकी मदद होनी चाहिए । इसलिए मैं यह भी मानता हूं कि बहुत सारे सोच वाले भाई यह सोचते हैं कि शहरों में राशनिंग हो और देहात का जो मजदूर है, जो हिन्दुस्तान का सबसे गरीब अंग है उसको राशनिंग की आवश्यकता नहीं, यह सोच ठीक नहीं है । यह सोच बिलकुल गलत है । मैं

समझ सकता हूं कि हमारे जैसे भाई जगवीर सिंह जैसे भाई जो पैदा करते हैं उनका अनाज और ज्यादा ले लें, लेकिन इसके साथ-साथ यह जरूर होना चाहिए कि देहात में जिनको खेत मजदूर कहते हैं, उनकी खरीदने की शक्ति बहुत कम है। तो राशनिंग सबसे पहले किसी के लिए होनी चाहिये तो उनके लिए होनी चाहिये। लेकिन राशनिंग आज किसके लिए होता है ?

उप-सभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : अब समाप्त कीजिए, हो गया।

श्री रणवीर सिंह : अभी समाप्त कर रहा हूं। जो मंत्रालय के सचिव हैं उनके लिए भी है, जो सदस्यगण हैं उनके लिए भी हैं, शहर में बड़े-बड़े साहूकार हैं, करोड़पति हैं उनके लिए भी है, लेकिन उस गरीब के लिए राशनिंग की सोच नहीं है। यह गलत है और इसको हमें बदलना चाहिए। सभापति जी मैं आखिर में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि भूख से हिन्दुस्तान में मरे थे आज से 30-31 साल पहले। वे हजारों की संख्या में नहीं थे जिस तरह से आज हजारों की बात की जाती है बल्कि उस वक्त 22-33 लाख भाई अकाल से बंगाल में भूख से मरे थे जिससे दुनिया को पता लगा था कि हिन्दुस्तान में कुछ हुआ है। आज तो हिन्दुस्तान की इज्जत ऊंची हुई है। हिन्दुस्तान में बंगला देश तक के लोगों को भूखों नहीं मरने दिया गया इन्दिरा गांधी सरकार ने। आप कितना ही प्रचार करें दुनिया में यह यकीन नहीं आ सकता कि इन्दिरा गांधी अपने देश के किन्हीं लोगों को भूख से मरने देंगी। यह अच्छी बात है जो राजनीति है उस राजनीति को परे रख कर आर्थिक नीति के ऊपर अपने विचार प्रकट करने चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि खेती की पैदावार के लिए हम जितना ज्यादा पैसा दें वह देश के हित की बात है। खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए जितने सरमाया पास होने की जरूरत है चाहे वह कपास हो, चाहे वह गुड़ हो, चाहे वह तोनी हो, चाहे वह गेहूं हो, चाहे वह चावल हो उसके लिए जितने सरमाया की जरूरत है उतनी देनी चाहिए। अगर हम नहीं देते हैं तो हम बिचौलियों के हाथ में खेलते हैं। बिचौलियों के हाथ से किसान को हमें बचाना चाहिए।

SHRI G. LAKSHMANAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Government of India does not accept that there are starvation deaths in this country for the simple reason that the Government of India believes in fate—it is the fate of a citizen to die of starvation and, therefore, he died. Sir, though we call our country a secular State, what do we do? As soon as the late Dr. Zakir Hussain became the President, he went and got the blessings of the Shankaracharya. He washed his feet and took that water. Our present President, Shri Fakhruddin Ali Ahmad, as soon as he was elected President, went to the Vinayak temple and got the blessings of Vinayak. Therefore, Sir, we believe in fate. That is why, in spite of the fact that starvation deaths are taking place all over the country because of the policy of the Government with regard to food, they are not prepared to accept it and they believe in fate. They believe that it is the fate of an individual to die of starvation and therefore, he has died. That is why they do not accept there have been starvation deaths.

Sir, our country has not advanced in spite of the four Five Year Plans because we have not given importance to agriculture. 65 per cent of our river water even today, after 27 years of independence, gets into the sea. And three-fourths of our cultivable land is still very barren and is not cultivated. And how can we expect that there cannot be starvation deaths? There shall be starvation deaths. Therefore, Sir, in planning, we must give importance to agriculture. And that is why, Sir, I am reminded of a couplet in Tamil :

"Uludundu vazhvaare vazhvaar
Matrellam tozhudundu pinselvar."

That means, those who plough the land are the real people who produce wealth. And all the other people have to follow them. This is from Thirukkural. But, Sir,

[Shri G. Lakshmanan]

what is the position of a peasant today in our country? Does he get a living wage? Is he able to make both ends meet? No. He is not able to get it. That is why, Sir, in this country, the living conditions of the peasant have not improved. My previous speaker is not here. He said that our Prime Minister is responsible for electrifying 1,50,000 villages. Of course, there are 7 lakh villages in the country. I would like to say, Sir, if the Prime Minister is sitting in that place, it is because of the Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Karunanidhi and the D.M.K. Therefore, this credit I can also take. When the Congress was split, when the official candidate for the Presidentship was contested by Mr. Giri, it was the D.M.K. which came to the rescue of the Prime Minister of India, Mrs. Indira Gandhi, to save her from that defeat. But for the votes of the DMK, Mr. Giri would have been defeated; that means Mrs. Indira Gandhi would have been defeated. Therefore, though we are a small Party and our Chief Minister is a small man, he took a correct decision to support the Prime Minister of India, Mrs. Indira Gandhi, and therefore Mr. V. V. Giri. You must know that only in the second counting of votes Mr. V. V. Giri, had won, and those votes were of DMK. Had we voted against him and supported Sanjiva Reddy, which was requested to by no less a person than the greatest politician of India, Mr. Rajagopalachari, and by Mr. Kamaraj and all the other people, the Prime Minister of India, Mrs. Indira Gandhi, would not have been the Prime Minister but somebody else would have become the Prime Minister of India, and the result would have been that in the front benches only people like M/s. Kamaraj, S. K. Patil, Atulya Ghosh and Nijalingappa would have been there, but all these people have been shunted out and only second and third rank people have become Ministers. That is also something for which DMK is responsible. Ours is a small Party.

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA (Karnataka): Has it improved the efficiency of the Central Government or has it come down? What has happened?

SHRI G. LAKSHMANAN: Sir, my predecessor took the credit for supplying so many pump sets whereas that credit should also come to us. We have made Mrs. Indira Gandhi the Prime Minister and therefore that credit comes to us.

Sir, with regard to river water disputes, for the past 25 years no dispute has been settled by the Government of India, though we say that we are an integrated nation or an intergrated country. For instance, Sir, this Cauvery water—I think Mr. Lakshmana Gowda will not oppose me—Cauvery is the only river in India where all the water is being utilised for cultivation purposes. If you go to Pumphar, you will not be able to say whether it is Cauvery itself because the entire water is being utilised by the peasants in Thanjavur district. Now a situation has arisen and the Chief Minister of Tamil Nadu has already sent a telegram and we have given a memorandum to the Food & Agriculture Minister, Mr. Jagjivan Ram, and he has said he would consider it. Now, 1,300 crores cusic ft. of water of Cauvery has been kept by the Karnataka Government and they say in the year 1972 agreement was reached between the Chief Ministers that within six months everything would be settled. They say that the period is over and therefore we need not give water to Tamil Nadu. This is here. Now, a Chief Ministers' Conference is going to be held. Why I say this is whether it is a question of water dispute or any other dispute, every State takes its own point of view only and does not approach the problem in a national way. What would happen if Cauvery water is not given to Tamil Nadu now? Then, definitely, Sir, 7,00,000 acres of land will get dry, and now the monsoon has also failed. That will affect the granary of the South—Thanjavur district is the granary of the South— and we will have to starve and there will be starvation deaths for which, I think, the Chief Minister of Karnataka will be held responsible. The Government of India is having a meeting of the Chief Ministers. I would appeal to the hon'ble Minister Shri Shinde—Mr. Jagjivan Ram is not here—to voice the grievances of the people of Tamil Nadu. Of course,

Mr. Urs, the Chief Minister of Karnataka is telling the people that after the construction of the channel he would require water for his State. But we immediately need water and we have told him that you please give us water to us on loan, but they are not prepared to give. In these things, the Government of India should not have a political approach to the problem. Their party is the ruling party in Karnataka and there is a feeling in Tamil Nadu that since the Chief Minister of Karnataka is doing it, since he belongs to the Congress Party; the ruling party is the Congress Party and in the Centre also, the ruling party is the Congress Party...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION, (SHRI ANNASAHIB P. SHINDE): There would not be any political approach in these matters.

SHRI G. LAKSHMANAN : That is the feeling of the people in Tamil Nadu. I have expresed the feelings of the people there. I am sure that as far as the Government of India is concerned, they would not have this approach. And I am thankful to Mr. Shinde for having assured me. This is the position with regard to Tamil Nadu.

With regard to electricity also, my predecessor was speaking so much. We have been having so many power cuts. Now 15 to 25 per cent of power cut has been given effect to from the 1st of December. We have been asking that the second mine cut in Neyveli should be taken up immediately. If it is not taken up immediately, this power cut will be there. There was a reference to pump sets. I am proud to say that as far as the pump sets are concerned, Tamil Nadu is at the top. 50 per cent of the pump sets are being supplied by Tamil Nadu only. In Tamil Nadu, except Cauvery we do not have any other source of water. Therefore, we are utilising this thing and so many pump sets are being given. We want electricity. Electricity is not available. We have also given electricity to all the villages in Tamil Nadu. We have given electricity to all the Harijan colonies. No Harijan colony is left out without electrification. Therefore, we want this electricity. The second mine cut in Neyveli should be taken up immediately by the Government of India. But if we do such things, will it be sufficient? No, the farmers and the nation must have a scientific approach to the problems facing the country. Unless and until the farmers and the nation approcah the problems in a scientific way, there cannot be any solution. We have not scientifically improved as far as our cultivation methods are concerned, like Japan and some other countries. We have not improved. Why? We believe that land is God; the land owner is the landlord. Our system is like that. Are we doing anything to break this system? We are not doing anything. Take Kumbh Mela. Prime Minister of India participates in Kumbh Mela where people come without dress. If anybody goes in the street without dress, he is arrested. But in Kumbh Mela people are coming. And they call it Nirvana. Prime Minister of India goes to encourage it. How will a scientific mentality, a scientific approach come to the social system in this country? The people who are in power, the people who are the leaders of the country, they must have a scientific approach, and the Prime Minister should not go to Kumbh Mela. She should say : "How can I go and see that ?" But by going there, she wants to tell the people that she is so God-fearing and she thus attends Kumbh Mela. And how many votes she gets from Kumbh Mela? Nearly 50 to 60 lakhs of votes are assured. This is the approach. Therefore, a revolution has to take place, not the revolution of the type Mr. Jayprakash Narayan think of; a revolution has to be brought in, a social revolution, in which the ruling party, the Congress Party can play a role. But will they play a role? They will not. That is why I asked why should the Prime Minister of India attend Kumbh Mela. Unless and until this social system is completely revolutionised in this country on a rational basis, any revolution, any reform that you

[Shri G. Lakshmanan]

may bring in, will not have any effect. Therefore, Sir, I say that the Government of India should approach this problem in a scientific way. That is what the Prime Minister Pandit Nehru taught the world. He wanted a scientific approach to the problems. Of course, he also went to attend Kumbha Mela. That is for votes purposes. These superstitions are to be removed when we say that landlord is the lord because he was good pious man in his last birth and because the other person was a sinner in his last *janama*, he has become the farmer. With this feeling, the farmers in our part do their work. This must be completely revolutionised. If I put my efforts, if I put my labour, I should also become like the other man. That is why he is your landlord and you are a land tiller. These things must be completely removed from this country. The ruling party says it is a secular State. What secularism is it? The secularism is, as I mentioned just now, Dr. Zakir Husain, after he becomes the President of India, goes and washes the feet of Shankaracharya and takes that water. Is it secularism ? Will we improve this country or any country which has attained independence ? China was very backward. Let us go and see it today. It does not mean that I accept the system of government there. They have revolutionised their country. They have revolutionised their people, their mental make-up and that is how they are going forward. Therefore, a social revolution is necessary now in this country to accelerate economic revolution. With these words. I thank you for the opportunity given to me to speak.

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal) : Mr. Vice-Chairman, Sir, more than one hundred and twenty-five years ago Karl Marx said that a spectre was haunting Europe. I say now a spectre is haunting India, the spectre of famine. The megalomaniacs, missionaries of death and almost the paid servants of monopolists, landlords. profiteers, hoarders, black money big traders and speculators are ruling at the Centre and on this Government squarely lies the responsibility for bringing the country to the verge of the abyss. Famine has become an in-built feature of our country today. Now, I heard it in the other House and I have seen Press reports and they say no one has died of starvation. Shri Jagjivan Ram says no one will be allowed to die of starvation. If they blindly say so, I say what more cruel joke could be played upon the people of India. What blatant lies could be peddled on the floor of Parliament ? Perhaps they are disciples of Shankaracharya and believe in Maya. They are saying to the people who have died of starvation : Ye, who have died, listen to us. You have not died of starvation. You were wellfed and wellhoused and if you have died that is your fault. Unfortunately, perhaps the dead souls do not hear. Now, Sir, in passing I will only say that the President of West Bengal Congress, Shri Arun Maitra, almost two and a half months back said that in one district of West Bengal more than 1,000 people have died of starvation.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : Mr. Niren Ghosh, I give you a factual information. I have received a telegram from him saying that the statement which is attributed to him is not correct. Please do not base your arguments on that.

SHRI NIREN GHOSH : Then, you have pressurised him.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE : It is very unfair.

SHRI NIREN GHOSH : Two and a half months back it appeared in the Press and you did not think it fit to contradict it. Now you say you have got a telegram. Wonderful. Who will believe You. None will believe it.

Now, let me come to the other points. According to reliable reports and estimates, more than one-third of the total population of India is affected by famine and starvation. The worst affected areas

and States are : West Bengal—12 out of 16 districts ; Assam, particularaly Goalpara District ; Gajarat—particularly Kutch and Saurashtra wherein 17 out of 19 districts are the worst affected and 15 million people are starving ; in North Bihar where half the population of the State lives, nine out of ten districts are severely affected and according to the Government's own admission, 550 people have already died of starvation in Kerala. Is it also a maya, an illusion ? In Orissa, at least ten million people are under starvation. About two months ago, Sardar Swaran Singh, the then Foreign Minister, said in Washington that not a single man had died of starvation in India, that the American papers had been exaggerating the depth of famine condition, etc. What is the use ? It is no use hiding the truth. It is very patent to the naked eye. Later, the Prime Minister also referred to this and also told the samething at the press conference in New Delhi. But on October 20, 1974, the Agriculture Minister, Shri Jagjivan Ram, declared that "I have already said that nobody will be allowed to die of hunger". In replying to the last debate on starvation in the other House, Shri Jagjivan Ram emphatically refused to admit the fact that people have died and are dying of starvation. Very recently, the Prime Minister has coined a new formulation on the causes of food scarcity in India. According to her, the Bangla Desh conflict in 1971 is mainly responsible for the crisis. It was in 1971. Now we are in 1974. Three years, 1972, 1973, 1974, have gone.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTRE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : What are you reading from ?

SHRI NIREN GHOSH : These are my notes. I collect these materials from your reports, Press clippings and all that.

So, I am bound to say that it is like the Roman proverb that when Rome was burning Nero was fiddling. The Official and Press reports are of no importance to the ruling Party. It is not accidental that the Washington Post of the USA, in a write-up dated October 27, had observed :—

> "With Mrs. Gandhi's popularity at its lowest level in recent years, the Government has ordered newspaper editors to keep famine stories and photographs off their front pages."

The New York Times dated 27th October had said that :—

> "anguished scenes are unfolding in the northern and the eastern India and famished children are digging grass, bark or roots to stay alive."

The Far Eastern Economic Review of Hong Kong, dated November 15, 1974 writes :—

> "India is trying its utmost to soft-pedal reports of famine in some parts of the country. New Delhi has sent strict instructions to the diplomatic missions abroad that they should blindly deny stories in the international Press saying that the problem is reaching serious proportions."

> "Envoys are required to tell foreign officials that the situation has been exaggerated in the media".

Sir, the American Times dated 15-11-74 writes :—

> "Henry Kissinger also discussed the question of food aid to India."

Mrs. Gandhi refuses to acknowledge publicly that thousands of people died of starvation in the States of Bihar and West Bengal. The Prime Minister having proudly proclaimed her country's self-sufficiency after a record harvest in 1971 "was reluctant to accept any aid that made India seem to be on the American dole again". Henry Kissinger nevertheless negotiated agreement which will provide 5 lakh to 1 million tonnes of grains at inexpensive prices on a long-term deferred payment basis. Not only that, according to information gathered from reliable sources import of food at concessional rates, PL 480, aid through backdoor, on government-to-government

[Shri Niren Ghosh]

basis arrangements are on the way to finalise the import of about 10 million tonnes through U.S. Multivational Corporation. I accuse the government. That is why this hush hush policy.

SHRI JAGJIVAN RAM : From which report you are quoting ?

SHRI NIREN GHOSH : From a reliable source. This is inside information of your government. I am not bound to disclose the source from which I get inside information of your government.

SHRI JAGJIVAN RAM: Will you please send that chit to me ?

SHRI NIREN GHOSH : Those who are party to this private discussion tell us. So it was the subject-matter of a discussion between Indiraji and Henry Kissinger. This is a serious accusation that I am making with full responsibility. How many crores will you spend ? Hundreds of crores of rupees to import food. You say it is secret information. And you said the other day that it is not in the public interest to disclose anything.

SHRI JAGJIVAN RAM : If you cannot disclose in public interest how can we disclose ?

SHRI NIREN GHOSH : All these years it was in the public interest to say so. Now that you are in fishy business entering into secret deals you are saying so.

Sir, the scarcity is man-made. According to Government's own admission the scarcity is only marginal. In reply to a question in the other House a few days ago, the Government gave the following figures.

In 1972-73, told production of cereals was 87.1 million tonnes, and the total import 6.97 lakh tonnes. In 1973-74, total production and total import were 93.9 million tonnes and 43.47 lakh tonnes respectively.

Per capita daily (average) availability of cereals, (as per Economic Survey 1973-74) in 1973 was about 350 grammes. In 1974, this availability must have gone up to more than 400 grammes per day, or more than 2,800 grammes per week.

In the statutory rationing areas, which do not cover more than 10 per cent of the total population, supply of cereals per week per card comes to less than 1800 grammes. Modified rationing scheme has become a paper scheme. Here the usual supply is 500 grammes per head per week and that too is irregular. The scheme does not simply exist. It has broken down. Where the rest have gone ? Why this acute crisis and famine condition ? Let the Government reply.

Take the case of West Bengal. Their paper 'Jugantar', belonging to their Minister, Mr. Tarun Kanti Ghosh recently wrote the following :

> "This year the output of paddy-cum-rice and wheat in the State was not too small..."

"Enough paddy-cum-rice was grown in the State to provide foodgrains at the ratio of 1602 grammes per capita per day. The shortfall caused by drought, flood, etc. is met from Central Pool. The Centre is providing about 1.6 million tonnes. Why then is there such a huge shortage of foodgrains ? Procurement may not have been up to the expectations. But where has the State's output of paddy and rice gone ?" This is a vital question. "Some say about 1 million tonnes of rice are still being secretly held by the hoarders and big farmers, and the Govt. has adopted a programme of dehoarding 1 lakh tonnes from this hoard. But is it now possible to dehoard this rice ?" The Yuva Congress or the Youth Congress dehoard from the FCI godowns and then take it back to the FCI godowns. A wonderful sort of dehoarding that the Indira Youth Congress is doing !

Out of a total production of nearly 6 million tonnes of rice in West Bengal and a marketable surplus of about 1.5 million tonnes, the State Government had dicided to procure only 5 lakh tonnes. And

they procured only 1,60,000 tonnes. This was inevitable as the Government was depending on the 'goodwill of the rice mill owners while the big farmers were depending on the Government's unwillingness and incapacity to hurt them'. Thus only about 40,000 tonnes were procured from the rice mills against a target of 3,60,000 tonnes. The State Government has occasionally talked of using the DIR, MISA, Essential Commodities Act, etc., to unearth and seize hoarded stocks; but nothing has been done; not a single finger has been raised in this matter. Similar is the picture in almost all the States. According to the All India Foodgrains Dealers' Association, more than 3 million tonnes of wheat have been cornered by the big producers in the wheat growing States. But the Association has not said that the traders are holding 10 million tonnes of foodgrains. This Government is very soft to them. This Government does not touch them. They have pumped Rs. 1,000 crores by increasing the foodgrain price at the official level. Exorbitant prices are being charged. When the harvesting is on, rice is being sold in Calcutta at Rs. 5 per kilo. So, another round of famine is round the corner. This dehoarding has been a farce. The Government has surrendered to the vested interests. The takeover of wholesale trade in foodgrains was a farce. The next day there was a wholesale reversal and surrender to the vested interests. The price has been increased. This is the state of affairs. They are like paid servants. They have taken black money for the elections. How can they hurt them? They cannot. They are servants of these one or two per cent vested interests.

The "Economic and Political Weekly", Bombay, dated 5th October 1974 writes under the caption "West Bengal—1943 Being Re-enacted": "Hunger and death are stalking vast parts of West Bengal today. The State's Relief Minister himself put the figure of starving population at 15 million. Spokesmen of the established political parties, including Ministers of the Congress, speak of starvation deaths by hundreds. Despite the Government's attempt to seal off Calcutta from the onslaught of the hungry villagers, the city's pavements and parks are cluttered with destitute families who have managed to sneak through the police vigilance. Hunger, of course, is a perennial experience with most people in rural West Bengal. But it has not been experienced on the present scale for 31 years, not since the terrible days of the autumn of 1943."

4.00 p.m.

Under the caption "Famine in West Bengal", Economic Times, dated 18-9-1974, editorially comments: "The spectre of the 1943 famine which had taken a toll of three million lives stalks West Bengal again; Calcutta streets are crowded with famished people picking crumbs of food from garbage. Whatever euphemism the State Government might prefer, the stark reality can no longer be ignored... More than one-third of the State's 45 million people are facing starvation. This time too the famine is partly man-made. Apart from nature's havoc, mismanagement of the economy and political ineptitude have led to a situation which could possibly have been prevented...There is obviously enough food in the country-side conveniently hoarded. And yet no serious dehoarding effort has been made".

According to various estimates, starvation deaths in West Bengal vary from 15,000 to 25,000. Cooch Bihar, Bankura, Purulia, Sundarbans etc. are worst affected...

SHRI MAHAVIR TYAGI: Within how many months?

SHRI NIREN GHOSH: Within the last four months. According to Jalpaiguri Congress, 500 starvation deaths were there in that district alone. In Sundarbans also there were 100 deaths. The number of starvation deaths in Cooch Bihar can only be guessed. A prominent journalist who recently visited the affected areas in Cooch Bihar writes the following in the Times of India:

SHRI MAHAVIR TYAGI : I hope the Minister, while replying, will either clarify or contradict these figures.

SHRI NIREN GHOSH : He will contradict.

This journalist writes :

"As I entered Cooch Bihar town last week, I was accosted by a man...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): Is he Shri Niren Ghosh ?

SHRI NIREN GHOSH :...who implored me for help in cremating a boy, all skin and bone. I soon learnt that such cases are only too common. Often bodies of victims are abandoned on the roadside, at railway stations, in school verandahs, BDOs' offices, village markets and even in the backyards of the private houses. At the present rate, they will soon stop counting the dead and official records will show nothing even to suggest that there was a disaster... The authorities have thought it necessary to organise official squads to dispose of bodies, often in batches."

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI JAGJIVAN RAM) : How many did he see himself ?

SHRI NIREN GHOSH : This journalist has visited the scene. Our Party exists there. Unfortunately for you, our Party still exists in all districts of West Bengal. This is from a journalist. He went there. This is his personal report. He visited the town and toured the entire district. The West Bengal Government did not think it fit to contradict this.

The Economic and Political Weekly dated October 5, 1974, writes :

In the fact of such collosal distress, the State Government has done little besides bustle around. Apart from frequent trips to Delhi by the Chief Minister and his Cabinet colleagues with a view to...

SHRI KOTA PUNNAIAH (Andhra Pradesh) : Wherefrom he is quoting ?

SHRI NIREN GHOSH : Times of India.

SHRI OM MEHTA : It is all fiction by Shri Niren Ghosh.

SHRI NIREN GHOSH : It is Maya as Shankara said. Mr. Om Mehta, you live in air-conditioned rooms and enjoy saucy dishes. You cannot think of these. Some years ago, you used to think of these Mr. Om Mehta. You talked about this years and years ago with somebody whom I do not want to mention.

Now you have become a Minister and so, you are talking in this vein. But I challenge : You accompany me and we will tour the portions and the areas I have mentioned and let us see the position. Are you ready ? I throw this challenge to you. If you dare, you accept this challenge.

Sir, in Assam, the total number of deaths is not less than 15,000. The public distribution system has gone ! The buffer stock in 1972 was 9 million tonnes. But in 1974 it has come down to 2.5 million tonnes ! (*Time Bell*). Within two or three minutes, I will finish, Sir, I have almost come to the end of my speech.

Sir, I wanted to substantiate my point by quoting facts and figures and did not want to speak just with emotion. How can this otherwise be substantiated? I have to mention here that about a hundred Congress MLAs have not paid their levies! And, Sir, how has this levy been fixed? One has to pay about twenty quintals. But these people have influenced the BDOs and, so, the levy has been fixed at just two quintals and even this small levy has not been paid by about a hundred Congress MLAs of my State! This is how the Congress is behaving. Then, Sir, about 70 per cent of the irrigation has gone waste. This is according to an economic survey conducted

recently. Only a microscopic section of the affluent and big landlords and rich peasants has drawn water from the irrigation sources and 70 per cent of the irrigation has gone waste and this is also according to the same economic survey recently made by an expert committee appointed by them. Therefore, Sir, I demand that the State of West Bengal should be declared a famine-stricken State; it should be declared a famine State. Sir, nowadays they never declare a State as a famine-stricken State. They simply say that it is a scarcity-affected State and they never utter the word 'famine' because the Famine Code enjoins upon the Government certain responsibilities which they are not prepared to discharge. So, I demand that all those areas that I have mentioned should be declared as famine-stricken areas. It is the responsibility of the Government to see that these areas are taken care of properly. Otherwise, how can you call yourself a progressive Government?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: Mr. Niren Ghosh, what is the crop condition there?

SHRI NIREN GHOSH: I am prepared to answer your question if you give me more time.

SHRI JAGJIWAN RAM : No.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI J. P. MATHUR): No, please.

SHRI NIREN GHOSH: I am prepared to answer everything point by point. Otherwise, if you do not give me more time, I will sit down.

Sir, I was demanding that all these areas should be declared as famine-stricken areas and the Government should discharge its responsibilities properly. Sir, I think the situation can be met if whatever production is there, if the entire surplus stocks with people having ten acres and more of wet land and 30 acres of dry land, if all these are commandeered even at the rate fixed by the Govt., that is, Rs. 74/- or Rs. 76/- per quintal. I should also say that distress sales are going on and some bonus should be paid to these people who are making the distress sales because it is the poor and medium peasants who make the distress sales at very low prices. I know of what happened last year. According to the report from which I have quoted the other things, last year the police hunted the market during the first few days of the harvest when the poor and medium peasants came to the market and took away their stocks. Therefore, Sir, if what I have said is done, I am sure that with the rationing in a modified from foodgrains can be provided at Re. 1/- per kilo to the people. This can be done if my proposal is accepted and acted upon.

Now, Sir, these famine-stricken areas and the other areas have not sufficient funds and they speak of lack of finance, in this connection, with regard to the recommendation of the Sixth Finance Commission, I make this proposal that 75 percent of the Central revenues in each financial year should be set apart and allocated to the States as finance from the Central pool.

The Centre can only disburse 25 per cent. Since the States have been left high and dry, then you talk of States lacking finance. Why not cut down the defence budget to half—from two thousand crores of rupees to one thousand crores of rupees? Why don't you do that? No. You will never give land to the landless. You will never do that. You will cheat them... (*Interruptions*). Whatever authoritative reports have so far been, nothing has been done. Forty per cent of the land is concentrated . . . (*Interruptions*). Now, if I talk of China, they will think it is blasphemy. But they are 80 crores. We are 55 crores. They were far more backward and far more poverty-stricken. But nobody says that 800 million people of China cannot get a square meal. They cannot get luxurious rich dishes, but nutritious dishes are available to all. Why is India in this position? Why is there a perpetual famine in this country? Except for a year or two, each year there are

[Shri Niren Ghosh.]

starvation deaths. As I said, famine is a built-in feature of our country. I say that a government which cannot feed and clothe the people has no right to exist. Further you are a minority government. You have got only 43 and 44 per cent of the votes. You cannot speak in the name of the people . . .

SHRI JAGJIVAN RAM: You can . . . (*Interruptions*)

SHRI NIREN GHOSH: I do not claim that I speak on behalf of all. I am humble enough. But you are arrogant . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): Please conclude.

SHRI NIREN GOSH: I am concluding. You are making politics out of starvation by doling out assistance here and there and making the people dependent on you. You are making politics out of the deaths of the people . . . (*Interruptions*). But let me tell you, leaders may come and go we will go, I will go, you will go, but hunger in India under your dispensation will remain. And I echo of the words of Nehru here, whom you call your leader—he is not my leader—who said : Hunger is the drill sergeant of the people. This hunger will remain. You may go on making politics out of it, but hunger will remain. Hunger is the drill sergeant of the people and the retribution will fall on you, and then you will know what is what.

[**Mr. Deputy Chairman** in the Chair]

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, I had no intention to participate in this discussion, but hearing my colleague from the same State from which I come, I am compelled to contradict him on many counts.

First of all, I do not deny that my State, West Bengal, suffers from an acute scarcity and acute drought. Consecutively for three years, we have been having droughts, and the State Government is trying its best, with the help of the Government of India, to combat that natural calamity. Not only with the help of the Government of India, but with the help of non-official agencies also, the State Government is trying to help the distressed people. It is highly exaggerated to say that 15000 to 25000 persons have died of starvation. I challenge Mr. Niren Ghosh...

SHRI NIREN GHOSH: I also challenge . . . (*Interruptions*). I have thrown a challenge. (*Interruptions*)

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Mr. Niren Ghosh, I never interrupted you when you spoke . . . (*Interruptions*)

Mr. Deputy Chairman, Sir, Mr. Niren Ghosh's party has no chance to come back to this august House. So this is the last time that he will be speaking in this House from those benches . . .

SHRI VISHWANATHA MENON (Kerala) : You have rigged the elections.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY : Wherever you have won, it was a fair and clean election held under the aegis of the Government of India . . . .

SHRI NIREN GHOSH : You have sufficient expertise in rigging elections.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Mr. Niren Ghosh, you spoke for half an hour. You should let me speak now. He was telling about M.L.As. belonging to my party not discharging their obligations and duties so far as levy and procurement are concerned. May I remind this august House that when Mr. Niren Ghosh's party was in the Government, what did they do about procurement? May I tell this august House that even today if you go to the rural areas, you will find Mr. Niren Ghosh's party telling people not to hand over their stocks to the Government? Sir, it is very easy to come here and say that my party has failed. Yes, my party has certainly failed to take appropriate steps to mop up all the surpluses. But it is not due to our Government machinery alone. They could have tackled the situation. (*Interruptions*) Please stop this running commentary). You should have the courtesy to listen to others. I listened to you for half

an hour patiently. Mr. Deputy Chairman, Sir, a responsible opposition always remembers how to oppose because they know that they are the alternative who may sit in the Treasury Benches next time. But Mr. Niren Ghosh's party is a desperate party which knows that never in their life they will come back to power. That is why, they are so wild in their allegations. That is why they are so irresponsible about their behaviour in the rural areas when they ask the people not to hand over their surplus grains to the Government. (*Interruptions*). The State Government of West Bengal did its best to procure as much quantity of foodgrains as possible, not only by mopping up the distress sale but also by levy and by procurement. We are responsible for some failures also. That is why we are plugging every loophole so that in future there is no such failure in procurement. Will Mr. Niren Ghosh extend his party's and his own co-operation in this? He will never do that He and his party will politicalise the whole thing and they will take advantage of this distress.

SHRI NIREN GHOSH : We offerred co-operation. But the hands of co-operation were shunned.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: I will remind you and through you to this House that even yesterday, a Youth Congress boy was killed by their associates in Durgapur. This is the condition. Even yesterday, a bright young man was killed by their supporters in Durgapur.

SHRI NIREN GHOSH : All the killings are taking place because of your people.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Mr. Deputy Chairman, Sir, from the Government side, we arranged hundreds of gruel kitchens. Can Mr. Niren Ghosh say that anywhere any effort was made by him or by his party to provide even a morsel of food for the distressed and downtrodden people? Nowhere. We organised gruel kitchens in hundreds because we would not allow anybody to die due to starvation. He comes forward with certain reports. I want to know what was he and his party doing to remove this distress? Nothing. It is very easy to come here and denounce the Government here and in the State. When it comes to actual practice, it is his party which came down over the small agriculturist for whom he is shedding tears and the landless labours. But when they were in Government, they did maximum damage to the lowest of the low, to the poorest of the poor. This is what he and his party stand for. About the subject before us for discussion alone scarcity, I do not deny that there is acute scarcity in my State. It is no use only giving a lecture over that. It is a question of implementing the schemes not only for relief but for prevention also so that it is never repeated again. We are trying our best to get help from the Government of India in our small & major irrigation schemes. We are also trying our best for equal distribution, at least, to the poorest of the poor. But Shri Niren Ghosh's Party are going there and creating difficulties for us to function. This is his love and affection for the people. And this is how they are trying to politicalise the whole issue. I object to this Sir, I also try to draw the attention of the Government of India to the need of my State. Yes, of course, the Government of India came forward to help us. And with the help of the Government of India, the State Government could tide over the distress. I congratulate the Government of India, specially the Food Ministry, the present Food Minister and Agriculture Minister for the help we got and still are getting from them. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister will reply now.

SHRI GUNANAND THAKUR (Bihar): Sir, just a few minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : May be, this time I will allow you five minutes. But it must be known that either your name comes through the Whip or there must be some order because I cannot allow one list from the Whip and then again allow the individual Members who are getting up.

SHRI GUNANAND THAKUR: Sir, I had requested the Whip already.

उप-सभापति महोदय, चूंकि बहुत इस पर बहस हो चुकी है और मैं नहीं चाहता हूं कि इतने कम समय में सम्पूर्ण देश की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा करूं, लेकिन मैं अपने आदरणीय खाद्य मंत्री जी से जरूर प्रार्थना करूंगा और इनका ध्यान बिहार के सूखा और बाढ़ ग्रस्त इलाकों की ओर खींचना चाहूंगा।

उप-सभापति जी, माननीय खाद्य मंत्री जी ने विपत्ति के समय, बाढ़ के समय स्वयं उत्तर बिहार का निरीक्षण किया था। वह पूर्णिया गये थे, दरभंगा गये थे, पटना गये थे और कई जगह गये थे और मुझे भी करीब डेढ़ महीना घूमने का मौका मिला है बाढ़ग्रस्त इलाकों में और जो वहां का दृश्य है, उस संबंध में अधिक नहीं कहूंगा लेकिन इतनी जरूर मैं अपने आदरणीय खाद्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा और कहूंगा कि अगर समय रहते मुस्तैदी से काम नहीं लिया गया तो बिहार में हजारों लोग भूख से मर जायेंगे। इस सम्बन्ध में मैं 14 तारीख के आर्यावर्त का उदाहरण देना चाहता हूं जहां फ्रंट पेज पर यह अंश आता है—उत्तर बिहार में अन्नाभाव के कारण घोर दुर्भिक्ष की स्थिति। किसान मजदूर शहरों की ओर भाग रहे हैं।

आज जो स्थिति हो गई है, चाहे वह कोसी नदी की बाढ़ हो, चाहे कमला नदी की, चाहे गंडक की बाढ़ हो, उत्तर बिहार एक वीरान जैसा लग रहा है। और भूमिहीन गरीबों, किसानों और मजदूरों को कोई काम नहीं मिल पा रहा है जिसके चलते जो आगामी फसल थी उसमें काम मिला नहीं, रबी की फसल के लिए केन्द्र ने 97 हजार क्विंटल बीज दिया और मैं सीड्स कारपोरेशन से थोड़ा संबंधित भी हूं, मैं बाबू जी का ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगा।

हम लोग 15-16 को पटना में थे। मुझ को पता चला कि बलाकों में किसानों को अभी तक सीडस नहीं मिला है। रबी का टाइम आ गया है। अगर किसान को हम सीड्स नहीं देते हैं तो रबी का भी समय निकल जाएगा। जो सीड कारपोरेशन के डीलर्स हैं उनका यह कहना है कि हम क्या कर सकते हैं बीज तो सरकार ने ले लिए और सरकार के माध्यम से ही वह बांटे जाएंगे। वहां से भी वह ठीक ढंग से मिल पाएंगे या नहीं मुझे इसमें भी डर है।

उत्तर बिहार की बात मैं करता हूं जहां बाबू जी स्वयं देख कर आए हैं। उत्तर बिहार के सहरसा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी के जो इलाके हैं उनकी हालत बड़ी दयनीय है। इस संबंध में मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार कुछ विशेष रूप से ध्यान दे। अभी हाल में जो 11 करोड़ रुपये की बीज बांटने के लिए केन्द्र ने दिया है इस बात के लिए उनको निगरानी रखनी चाहिए कि वह पैसा बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो और वह भूमिहीनों को ही दिया जा सके।

मैं एक बात की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं वह यह है कि जब तक लैंड टू दी डीलर्स, जमीन जोतने को नहीं मिलेगी तब तक वह जमीन से मोहब्बत नहीं रखेगा। बड़े लोगों को, बड़े जमीदारों को, बड़े भूपतों को बेनामी कब्जा किये हुए हैं। अगर सैंकड़ो एकड़ जमीन में से 50 एकड़ जमीन नहीं उपजेगी तो उनको कोई चिन्ता नहीं होगी। लेकिन छोटे-छोटे किसान, भूमिहीन किसान महरूम हो जाते हैं।

अभी नीरेन घोष जी कह रहे थे बंगाल में भूख से लोग मरे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब अंग्रेज की हुकूमत थी बंगाल में लाखों लोग मर गए थे और उस समय 16 रुपये का एक सेर, 20 रुपये का एक सेर चावल मिलता था। आज हमें इस बात का गर्व है, फख्र है कि इस हुकूमत में दो रुपये किलो भी चावल हुआ, 3 रुपये किलो भी चावल हुआ लेकिन इन्सान भूख से नहीं मरा। इस बात के लिए हम यह भी कहेंगे कि पता नहीं बाबू जी के चरण में क्या लिखा है। जिस विभाग में वे जाते हैं प्रकृति उनको मदद करती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम यह चाहते हैं विरोधी दल अपना सहयोग इसमें दें। यह खाद्य समस्या कोई दल की समस्या नहीं है यह समस्या हमारी, आपकी सबकी है। इसको

हमको, आपको मिलकर हल करना है। दलगत भावना से ऊपर उठ कर इसको हल करना है। मैं चाहूंगा कि अगर खाद्य समस्या को हल करना है तो लैंड टू दी टीलर्स का भी नारा देना चाहिये और उसके लिए हमें प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि इम्पलिमेंट हो सके। बहुत से राज्यों में 20-20 साल से कानून बने हुए हैं लेकिन गरीबों को जमीन नहीं मिल सकी है। यहां तक कि भूदान की हुई जमीन भी, यानी जिसको लोगों ने दान किया है, जिसको बहुत खराब जमीन कह कर दान किया है वह भी जमीन गरीबों के कब्जे में नहीं होने दी गई है।

यह अच्छा ही हुआ कि कृषि सिंचाई और खाद एक जगह कर दिया गया है। इससे रबी की फसल ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न हो जाएगी। मैं चाहूंगा इसके लिए आप जरूर अधिक से अधिक बीज और सिंचाई की व्यवस्था करें। मैं प्रार्थना करूंगा कि जो बड़ी-बड़ी देश की जो योजनाएं बनीं हुई हैं, जैसी कोसी योजना ; उसकी छान-बीन होनी चाहिए। कितना नैट उससे हमको प्रोफिट हुआ है और कितनी जमीन का हमारा टारगेट है और कितना इन्वैस्टमैंट हुआ है। सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि हम रुपया देते जाएं और इन्वैस्टमैंट होता जाए और आउट-पुट कुछ न हो। इसलिए मैं चाहूंगा कि देश में जो परिस्थिति गम्भीर है जैसे बंगाल में, असम में गैया-और भागों में उसको तो हमें ठीक करना है। रबी का समय आ गया है इसलिए हम सब लोगों को एक जुट हो कर काम करना चाहिए और सरकार को चाहिए कि गरीबों के लिए छोटे-छोटे किसानों के लिए अधिक से अधिक बीज और खाद की और सिंचाई की व्यवस्था करें। उत्तर बिहार से जो लोग छोड़कर भागे आ रहे हैं उन लोगों के लिए अधिक से अधिक हर प्रकार की सुविधा दें। उनके लिए कोई योजना बनाई जाए। मैं प्रार्थना करूंगा कि जो इलाके बाढ़ से पीड़ित हैं पिछले कई वर्षों से तटबंधों के बीच में लगभग 5 लाख किसान घिरे पड़े हैं ऐसे लोगों के लिए शिक्षा माफ होनी चाहिए।

लगान वहां पर माफ होनी चाहिए। मैं यह भी चाहूंगा कि वहां पर जो रिलीफ की व्यवस्था की गई थी वह मुश्किल से एक महीने के लिए भी नहीं मिली। मैं वहां पर घूमकर और दौरा करके आया हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इन सारी बातों की छानबीन करें। बिहार के अखबारों के अन्दर यह खबर भी छप रही है कि वहां पर चार और पांच लाख टन अनाज बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर पड़ा हुआ है और वह उठाया नहीं जा रहा है। आज इस विपत्ति की बेला में यह स्थिति अच्छी नहीं है। बाबू जगजीवन राम जी खुद ही बिहार की स्थिति को देख कर आए हैं। मेरा यह निवेदन है कि बिहार की गरीब, निरीह और पीड़ित जनता को बचाने के लिए शीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए और रबी की फसल को इस प्रकार से सफल बनाया जाना चाहिए ताकि हम अपने देश की कमी की स्थिति को समाप्त कर सकें।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री जगजीवन राम): उप-सभापति जी, सदस्यों ने इस संबंध में जो चिन्ता प्रकट की है, मैं मानता हूं कि यह स्थिति ऐसी है जो चिन्ता का विषय बन सकती है। लेकिन जब श्री नीरेन घोष ने कहा कि अब बंगाल को फैमिन एरिया घोषित करो तो मुझे ऐसा लगा कि बंगाल की स्थिति की उनको बिलकुल जानकारी नहीं है। यह इसलिए कि बंगाल में धान की फसल इस साल इतनी अच्छी है कि अगर यह कहा जाय कि वह देश में सब जगह से अच्छी है तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी और खुशी की बात यह है कि . . .

SHRI NIREN GHOSH: Why is rice being sold at Rs. 5 a kilo?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please have patience to hear the Minister.

श्री जगजीवन राम: वहां पर धान की कटाई आरम्भ हो गई है और चावल बाजार में आने लगा है और मेरे मित्रों को इस बात की जानकारी होगी कि चावल के दाम में जो गिरावट आई है उस स्थिति में फिर वह यह कहें कि बंगाल को अकालग्रस्त घोषित करो तो यह कोई समझदारी की बात होगी, ऐसा मैं अनुभव नहीं करता।

उप-सभापति जी, इन्होंने कुछ आंकड़े बताये हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। जब कभी प्राकृतिक प्रकोप हो जाय, बाढ़ की वजह से हमारी फसल नष्ट हो जाय या वर्षा के अभाव में फसल नष्ट हो जाय या अन्य कोई भी विपत्ति आती है तो उसके कारण सबसे पहले उन लोगों को परेशान होना पड़ता है जो समाज के गरीब वर्ग के लोग हैं। उसमें सभी बिरादरी के लोग आते हैं। कोई ऐसी जाति नहीं है जो कह दे कि उसके अन्दर गरीब लोग नहीं हैं। इसलिए यह प्रश्न गरीबों का प्रश्न बन जाता है। वैसी परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए दो तीन ही रास्ते हैं और अफसोस की बात यह है कि हमारे देश के अधिकांश बुद्धिजीवी लोग हैं वे समस्या की जड़ में जाते ही नहीं हैं। इसका कारण यह भी है कि वे लोग विदेशों में प्रकाशित पुस्तकें पढ़कर अपने नियम बनाते हैं। उप-सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि अन्न का भंडार पड़ा हो और किसी व्यक्ति के पास उसे खरीदने के लिए पैसा न हो तो ऐसी स्थिति में अन्न की कमी से या भूख से आदमी मरा है, ऐसा कहा जा सकता है? अपको स्मरण होगा, सन 1967 में जब ऐसी ही स्थिति थी तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई थी। मुझे अपने आपको कुछ बधाई देनी होगी, अगर मैं यह कहूं कि दुनिया के लोगों ने इस बात को कबूल किया कि हिन्दुस्तान ने इतनी भयंकर स्थिति को बहुत सफलतापूर्वक निभाया है। आज की स्थिति सन् 1967 की स्थिति से अधिक भयंकर नहीं है और इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस स्थिति का सफलता के साथ मुकाबला किया जा रहा है।

उस समय भी मैंने उस वक्त के जो हमारे खाद्य के सचिव थे, और आजकल वे बंगाल के गवर्नर हैं, एक ही बात कही थी कि उन आपद्ग्रस्त क्षेत्र के लोगों को अगर हम कुछ क्रय-शक्ति दे दें तो कोई मरने नहीं पाएगा। और यही हमारा मूल मंत्र था 1967 में सफलता हासिल करने का। मैंने सभी राज्य सरकारों से कहा कि कठिन श्रम की योजना, सहज श्रम योजना और खाने पीने के लिए कर्ज देने की जरूरत पड़ी तो वह भी कंजम्शन लोन दें। हमारी कुछ सामाजिक परंपराएं हैं, बंधन हैं। कुछ लोग कठिन श्रम योजना नहीं कर सकते हैं इसलिए नहीं कि उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है; बल्कि समाजी बनावट ऐसी है कि अगर वह ऐसा करें तो समाज में उनके साथ उपहास किया जाएगा। उनके लिए सहज श्रम योजना आवश्यक होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन दोनों तरह के कामों को नहीं कर सकेंगे। उनको भी कुछ क्रय-शक्ति देना आवश्यक हो जाता है। तो वहां कंजम्शन लोन देकर वह शक्ति दे सकते हैं। अगर क्रयशक्ति आ गई तो दावे के साथ कह सकता हूं हमारे मुल्क में कोई भूख से मर नहीं सकेगा और इस काम को इस साल शुरू किया गया है। मैंने तो अभी हाल में इसकी जिम्मेवारी ली है; परिस्थिति पहले से बिगड़ी हुई थी।

उपसभापति जी, यह भी मालूम होना चाहिए कि जब मैंने इस मंत्रालय को छोड़ा था तब 90 लाख टन के रिजर्व अनाज को छोड़ कर आया था और उसी अनाज से 3 साल की लगातार अनावृष्टि से जो समस्या पैदा हुई उसका मुकाबला हम कर सके हैं। तो ये तीनों योजनाएं चल रही हैं। जहां जहां बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र हैं या सूखे से ग्रस्त क्षेत्र हैं या अभावग्रस्त क्षेत्र हैं वहां लोगों को राहत पहुंचाई गई है जहां बरसात की वजह से पानी की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो गई, जैसे उत्तर बंगाल में या उत्तर बिहार में कोई भी कठिन श्रम योजना लगाना संभव नहीं था, तो उस वक्त मुफ्त में लोगों को खाना दिया गया। जो खाने को उस किचन में आकर नहीं खा सकते थे, ऐसा भी प्रबंध किया गया, कि सस्ते दाम में रोटियां दी जाएं जो कि ले जाकर के परिवार के साथ खा सकें।

यह बात स्मरण रखनी है उपसभापति जी और माननीय सदस्यों से मैं कहूंगा यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि हिन्दुस्तान गरीब

देश हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हम भी विकसित देश हो जाएं । हम विकासोन्मुख हैं । यह भी कहते हुए हमें संकोच नहीं होना चाहिए कि सामान्य परिस्थिति में भी देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको दोनों शाम क्षुधा की तृप्ति नहीं होती है । बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पाता है । तो ऐसी स्थिति में परेशानी उनको बहुत रहती है और जब यह प्राकृतिक प्रकोप हो जाता है तो उनकी परेशानी और भी बढ़ जाती है, उनके कष्ट और भी बढ़ जाते हैं, उनकी डिस्ट्रेस और भी बढ़ जाती है—इससे इन्कार कौन कर सकता है ? लेकिन जब ऐसा नाजुक समय होता है तो अपनी कठिनाइयों का अतिरंजन कर देने से कठिनाइयां कम तो नहीं हो पाती हैं । कठिनाईयों के अतिरंजन से हम लोगों की कठिनाई को बढ़ा देते हैं । यह स्मरण रखना चाहिए, खाद्य का मामला बहुत नाजुक है । हम अभाव-अभाव कहने लगें तो अभाव हो सकता है । मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहूंगा इस नाजुक मामले को बिगड़ने नहीं देना चाहिए ।

यह फिर अपने आप को धन्यवाद देना होगा उपसभापति जी, जब मैंने यह जिम्मेवारी ली तमाम मुल्क में एक विश्वास पैदा हो गया है, मुल्क में एक विश्वास आया है और दामों में गिरावट आई है और उसमें बढ़कर यह बात हुई है, जब किसी से बातचीत करता हूं, चाहे बम्बई के, कलकत्ता के, दिल्ली के लोग हैं जिस तबके के लोग हों, कहते हैं कि चीजें मिलने लगी हैं । जहां ऐसा हो गया था कि चीजें मिलती नहीं थीं, दाम देने पर भी, अब वह मिलने लग गई हैं—चाहे वह चीनी का प्रश्न हो, डालडा का प्रश्न हो, गेहूं का प्रश्न हो, चावल का प्रश्न हो ; देहात के क्षेत्र में भी शहर के क्षेत्र में भी । जिस सूबे से हमने मालूम किया हर सूबे को उतना अन्न देने का प्रयत्न किया जिससे वहां की परिस्थिति का मुकाबला किया जा सका ।

श्री गुणानन्द ठाकुर : बिहार को कहां मिला ?

श्री जगजीवन राम : एक बात जरूर है कि राज्य सरकारें इतनी मांग कर देती हैं जिस मांग की आवश्यकता नहीं होती ।

हमारा अनुभव पिछली दफा का है और इस दफे के अनुभव से भी हम यह समझते हैं कि जितनी आवश्यकता है, उतना हम देते हैं; देश में जो प्राप्त किया गया है और विदेशों से जो मंगाया गया है, उसी में से राज्यों को दिया जाता है । निरेन घोष ने कहा कि विदेश से अनाज मंगाने की बात को चुप चुप रखना चाहते हो । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें चुप चुप रखने की क्या बात है । आप क्यों समझ लेते हैं कि आपकी जो काम करने की शैली है, वही हमारी भी शैली है ? वह हमारी शैली नहीं है ।

SHRI NIREN GHOSH: You give us the figures and also the amount.

श्री जगजीवन राम : मैं फिगर्स नहीं दूंगा । अगर आप हमारे पास आयेंगे तो मैं बतला दूंगा । लेकिन यह कहना कि हम अमेरिका से चुप चुप करके अनाज ले रहे हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि क्यों चुप चुप करके लेंगे ? अगर हमें देशवासियों को खिलाना है और उसके लिए बाहर से अनाज मंगाने की आवश्यकता है, तो हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम अनाज मंगाएंगे और चुप चुप कर नहीं मंगायेंगे और जहां से मिलेगा वहां से मंगायेंगे । जो लोग अमेरिका के गेहूं को अपवित्र समझते हैं वे खाना छोड़ दें तो मुझे अफसोस नहीं है । अगर वे अमेरिका के खाद्यान्न को अपवित्र और अस्पृश्य समझते हैं तो. . .

श्री महावीर त्यागी : अमेरिका का गेहूं तो लाल होता है ।

SHRI NIREN GHOSH : You are contradicting. I said, from the multi-national corporations you are going to purchase.

श्री जगजीवन राम : मल्टी नैशनल कार्पोरेशन से भी लेंगे और बाइलिटरल इंतजाम करके भी लेंगे और जहां पर भी देखेंगे कि राहुलियत के साथ मिल रहा है बिना शर्त के, वहां से हम लेने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

SHRI NIREN GHOSH : Give us the entire picture.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is giving you.

श्री जगजीवन राम : इसलिए बाहर से मंगाकर भी आज जो हमारी वितरण की शैली बन गई है, जितना हम लोगों को वितरण कर रहे हैं, उसको चलाना चाहते हैं ।

...

खुशी की बात तो यह हुई है कि पिछले महीने जो वर्षा हुई है, उससे किसानों के भीतर एक नया विश्वास आया है और एक नया भरोसा आया है । मैं बतला देना चाहता हूं कि इससे सरकार के जो राहत के काम चल रहे थे, उसमें भी सुविधा आ गई है । सुविधा का अर्थ यह है कि जब किसान कार्तिक की फसल बोता है, अगर उसके पास अपने साधन न हों, तब भी किसान का हृदय ऐसा होता है कि वह अपने खेत को आबाद करने के लिए अपने जेवर बन्धक रखकर उस काम को कर लेता है । जो उसके काम करने वाले श्रमिक होते हैं उनकी भी वह चिन्ता कर लेता है । तो यह स्थिति ऐसी पैदा हुई है कि हिन्दुस्तान के प्रायः सभी राज्यों में संतोषजनक वर्षा होने की वजह से रबी की फसल की अच्छी उम्मीद बन गई है ।

उप-सभापति जी, आपको मालूम हो कि जब किसान को यह मालूम हो जाता है कि अगली फसल की उम्मीद अच्छी है, तो उसके घर में जो कुछ जरूरत से ज्यादा अनाज होता है वह बेचने के लिए निकाल देता है । खासकर के गेहूं के मामले में तो इस समय अगर एक महीने की भी देरी की तो गेहूं के बरबाद हो जाने का भय रहता है । लेकिन यह बात हमारे यहां के बहुत लोगों को मालूम नहीं है पर किसान यह बात जानता है इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को अपना गेहूं निकालना ही पड़ेगा । जो बड़े-बड़े किसान हैं उनके पास गल्ला है । मुझे कुछ बड़े किसानों से इस बारे में सूचना मिली है और उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं । किसी किसी क्षेत्र के किसानों को भरोसा और विश्वास हमारे में है और उन्हीं में से कुछ लोगों ने कहा है कि फलां, फलां केन्द्र हैं और वहां के किसानों के पास गेहूं है । मैंने राज्य सरकारों के पास खत लिखा है कि बड़े बड़े किसानों से अनाज निकालने का प्रयत्न होना चाहिए । मैंने यह भी कहा है और मैं इस बात को फिर दोहरा देना चाहता हूं कि भारतवर्ष का किसान देशभक्त है । भारतवर्ष का किसान निरक्षर हो सकता है, लेकिन बेअक्ल नहीं है । उसके पास साधारण बुद्धि होती है और मैंने यह भी कहा था कि किसान चन्द रुपयों के लिए समाज के लोगों को परेशान करना उचित नहीं समझता है । मैं मानता हूं कि इसका कुछ असर हुआ है । राज्य सरकारों को मैंने यह भी कहा था कि अनुरोध करने से, निवेदन करने से अगर यह गल्ला नहीं निकलता तो कानून की जितनी शक्ति हमारे पास है सब का उपयोग करके इसको गल्ला निकालना चाहिए, डिफेंस आफ इंडिया ऐक्ट का इस्तेमाल करके, एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट का इस्तेमाल करके और आवश्यकता पड़े तो मीसा का इस्तेमाल करके । मुझे यह कहते हुए सन्तोष है कि इन प्रयत्नों के फलस्वरूप करीब एक लाख टन गल्ला बाहर निकाला जा चुका है और हमारे ये प्रयत्न जारी हैं । हमें उम्मीद है कि बहुत ज्यादा कानून का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, किसान स्वेच्छा से अपनी आवश्यकता से अधिक जो गल्ला उनके पास है उसको निकाल देंगे ।

चैत्र की फसल मार्च-अप्रैल तक कटेगी, मई तक बाजार आ जायगी । जिस मिकदार में राज्य सरकारों को हम सहायता कर रहे हैं— वह फिगर देने की आवश्यकता में नहीं समझता, लोगों को मालूम है—उसी हिसाब से अभी चलाना चाहते हैं । जहां-जहां अगहनी की कटनी हो रही है, धान आ रहा है, वहां राहत कुछ अधिक पहुंच रही है । इस समस्या का मुस्तकिल समाधान यही हो सकता है कि प्रकृति का कठिन से कठिन प्रकोप हो जाये, अनावृष्टि हो जाय, वैसी हालत में भी हम अपने देश में उतना अनाज पैदा कर लें जितना अपने देशवासियों को खिलाने के लिए आवश्यक है । मेरा प्रयत्न इसी दिशा में होगा । पहले दिन, उपसभापति जी, जब मैंने इस मंत्रालय का भार ग्रहण किया तो अपने अफसरों से यही कहा था कि भारत के लिए वह शुभ दिन होगा जिस दिन केन्द्र में खाद्य विभाग नहीं रहेगा ।

आज हम करते क्या हैं खाद्य विभाग से ? कुछ राज्य सरकारों को तकाजा करके कहते हैं कि प्रोक्योरमेंट कर लो, वसूली कर लो, अनाज का भंडार बना लो, जो तुम्हारी आवश्यकता से अधिक है वह केन्द्र के भंडार में दे दो । यह सब करने के बाद भी जब साल भर खिलाने के लिए कम पड़ता है तब प्रयत्न करते हैं कि विदेश से मंगा कर अपना भंडार बना लें । केन्द्र में खाद्य विभाग की आवश्यकता इसलिए है कि जितना हम खाते हैं उतना पैदा नहीं कर पाते हैं ; उतना पैदा कर लेते तो उसकी जरूरत नहीं रह जाती । खाद्य पर या वितरण पर नियंत्रण की आवश्यकता तभी होती है जब हमारे यहां अभाव की स्थिति होती है । जब अभाव नहीं रहता है तो मैंने इसका अनुभव किया 1969 में कि दिल्ली में खाद्य का नियंत्रित वितरण टूट रहा है, लोग ही वहां नहीं जाते । जब बाजार में खुलेआम मिलेगा तो कोई फेयर प्राइस शाप पर और राशन की शाप पर नहीं जाएगा ; वहां जाएगा जहां दो-तीन किस्मों की चीज को देख कर, चुन कर ले सके, चाहे चार पैसा ज्यादा देने पड़े । यही मनुष्य का स्वभाव है । लेकिन हमको हर स्थिति के लिए प्रबंध करना पड़ेगा ।

मैंने यह तय किया है कि सिंचाई सम्बन्धी उन योजनाओं को पूरा करने का यत्न किया जाए जो जल्दी फल दे सकती हैं ।

SHRI MAHAVIR TYAGI : Congratulations. This is the only solution.

श्री जगजीवन राम : जहां पानी के बंटवारे के मसले को लेकर राज्य सरकारों में मतभेद है मैं प्रयत्न करूंगा कि उसको जल्दी से जल्दी सुलझा दिया जाए । छोटी और मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं को भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, यह भी हमारा प्रयत्न होगा । यह बात सबको मालूम है कि आज हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन इस तथ्य को भी भुलाया नहीं जा सकता कि हमारा आर्थिक तंत्र बहुत अंश में कृषि पर निर्भर है । जिस साल फसल अच्छी हो जाती है देश के अर्थशास्त्री कहने लगते हैं कि अब देश की अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है ; जिस साल कृषि की उपज कम हो जाती है अर्थशास्त्री कहने लगते हैं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था ढीली हो रही है । मैं ऐसा मानता हूं कि अभी कई-एक दशक तक हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था कृषि पर निर्भर करेगी । कृषि आज भी हमारे राष्ट्र की आय का एक बहुत बड़ा अंश देता है ।

आधे से थोड़ा ही कम । कृषि ऐसा उद्योग है हमारे देश का जिससे आज भी, इस हालत में भी 80-82 प्रतिशत लोगों का निर्वहन हो रहा है इंप्लायमेंट के हिसाब से । इसलिए कृषि को जितना तेजी से हम सशक्त बना सकें और सक्षम बना सकें उतना ही देश को हर ड्रिप्ट से लाभदायक होगा ।

मेरे मित्र नीरेन घोष ने कहा कि डिफेंस के बजट को कम कर दो । मैं उनकी सलाह को मान लेता अगर किसी सूचना के आधार पर ऐसा उन्होंने कहा होता । सूचना का आधार यह कि हमारे उत्तर पूर्व की सीमा पर, मैंने चीन का जिक्र किया था, चीन है । हमारे प्रयत्न करते रहने पर भी, हमारे विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री के मित्रता का हाथ बढ़ाने के बावजूद भी चीन का हाथ उस हाथ को पकड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ा है । वैसी हालत में कोई भी देशभक्त जो मातृभूमि की सरहद की सुरक्षा चाहता है, डिफेंस के बजट में कमी करने की इस वक्त सलाह नहीं दे सकता । इसलिए मेरी मजबूरी है । लेकिन कृषि और सिंचाई के लिए सारे मुल्क की आर्थिक अवस्था को मद्दे नजर रखते हुए जितना अधिक से अधिक हम लगा सकते हैं, लगाने का यत्न करेंगे क्योंकि मैं जानता हूं कि वही एक रास्ता है जिससे खाद्यान्न के मामले में हम देश को स्वावलम्बी बना सकते हैं सिर्फ खाद्यान्न ही नहीं, जब कृषि के मामले में मैं सोचता हूं तो आपको मालूम है, उप-सभापति जी, कि हमारी कृषि से न सिर्फ लोगों को खाने को मिलता है, हमारे देश के कई बड़े-बड़े उद्योग कृषि के ऊपर निर्भर हैं जिनमें राष्ट्रीय सम्पत्ति से अभिवृद्धि तो होती ही है, साथ ही साथ बहुत से परिवारों का निर्वहन होता है उन उद्योगों में काम धन्धा करके । उदाहरण देना हो तो दे तीन दे दूं । टैक्सटाइल हैं, कपड़े के कारखाने हैं, वह

रुई के ऊपर आधारित हैं, कपास के ऊपर आधारित हैं। जूट के कारखाने हैं, जिससे हम बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा अर्जन करते हैं, वह भी कृषि के उत्पादन पर निर्भर है। चीनी के कारखाने ले लीजिए। चीनी का उद्योग चलता है तो वह भी कृषि से उत्पन्न होता है। मैंने दो-तीन बातों का नमूना पेश किया। सोचा जाए तो बहुत सी चीजें हैं। वनस्पति है, वह भी कृषि के ऊपर निर्भर करता है। तो खाद्यान्न और देश के कई बड़े उद्योगों को कच्चा माल देना हमारी कृषि की उपज के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कृषि को प्रोत्साहित करना पहला काम है।

छोटे किसानों की बात हुई। बिहार में बाढ़ आई तो बिहार में ही नहीं आई, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, उत्तर बिहार में, उत्तर बंगाल में भी आई। मैं उस वक्त कृषि मंत्री नहीं था, लेकिन मैंने तीनों जगह हवाई-जहाज से देखा, कहीं कहीं उतरा भी और इस साल की बाढ़ की स्थिति इसलिए भयंकर थी कि पहले जब बाढ़ आती थी तो दो तीन दिन में पानी निकल जाता था, लेकिन इस साल पानी को उन इलाकों से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि वह जाने का नाम ही नहीं लेता था। इसका नतीजा यह हुआ कि जो धान की फसल खड़ी हुई थी वह गल गई। किसान के घर में जो कुछ था वह बह गया। अजीब हालत प्रकृति की है। पता नहीं कभी प्रकृति भी अकल से काम लेना सीखेगी या नहीं। लेकिन यह तो हुआ जहां पानी था। जहां वृष्टि थी वहां बरसता गया, जहां पानी नहीं था, जैसे बिहार का दक्षिणी भाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात ये सब वृष्टि के अभाव में परेशान थे, ऐसा लगने लगा था कि थोड़ी देर और पानी नहीं पड़ता तो लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा चाहे सौराष्ट्र हो, कच्छ हो, राजस्थान हो और बिहार का दक्षिणी हिस्सा हो या मध्य प्रदेश हो वहां पानी नहीं बरसा। जो असम कुछ चावल केन्द्र को देता था उसे आज केन्द्र से खाद्यान्न लेने की आवश्यकता हुई, केन्द्र ने उनको दिया। असम की एक और स्थिति है और कुछ पश्चिमी बंगाल की भी। उसके बारे में कुछ इशारा कर देना चाहता हूं। बंगला देश का निर्माण हुआ। भारत का उसमें योगदान रहा। लेकिन कई वर्षों से पाकिस्तान का निर्माण होने के बाद से उस समय के पूर्वी बंगाल के साथ जिस तरह व्यवहार होता रहा वह इतिहास की बात है। पाकिस्तान ने वहां से जाने से पहले जिस तरह से बंगला देश की सारी आर्थिक अवस्था को नष्ट-भ्रष्ट कर गया था वह भी इतिहास की बात है। वहां से परेशान होकर भी कुछ लोग आए हैं पश्चिमी बंगाल में और असम में भी। इतना इंगित कर देना मैंने आवश्यक समझा। जो आते हैं बुरी हालत में आते हैं।

मैं कह रहा था कि पश्चिमी बंगाल में बाढ़ की स्थिति रही है। हमने यह भी देखा इस साल लोग परेशान रहे हैं। अगर समय रहते हम रबी की बुवाई का अच्छा इन्तजाम कर लें तो आने वाली रबी की फसल तक हमको राहत मिल जाएगी। इसको देखते हुए हमने एक अफसर को तैनात किया है। जो खाद को, बीज को और क्रैडिट को यानी इन सब चीजों को संभालेगा। अफसर को यह भी हिदायत दी गई है कि वह इससे ही सन्तोष न कर ले कि फलां राज्य को इतनी खाद एलाट कर दी है, फलां राज्य को इतने बीज एलाट कर दिए हैं बल्कि यह भी टेलिफोन करके सूचना लेनी चाहिए कि हर राज्य की सरकार के पास खाद पहुंच गई या नहीं बीज पहुंच गए या नहीं। डिस्ट्रिक्ट में चले गए या नहीं और डिस्ट्रिक्ट से ब्लाकों में गए या नहीं। यह सब मैंने करवाया। बिहार के मामले में भी मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने खाद और बीज ब्लाक में पहुंचा दिए हैं। वहां के रेवेन्यू कमिश्नर आए थे उन्होंने आते ही यह खबर दी है कि यह सब चीजें ब्लाक तक पहुंच गई हैं। यह मैंने इन्तजाम किया है।

यह भी खुशी की बात है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री दोनों ने कहा है कि इस दफा बादल ने अकल से काम लिया है। राजस्थान में जहां रबी की फसल होनी है वहां अच्छा पानी पड़ गया। गुजरात में, सौराष्ट्र में, कच्छ, बनासकांठा में भी अच्छा पानी पड गया। छतीसगढ़ में जितना पानी होना चाहिए था उतना

पानी नहीं पड़ा। असम और बंगाल में रबी का प्रोग्राम बन गया है। कितनी खाद चाहिए, कितने बीज चाहिए और कितना क्रैडिट चाहिए यह सब वहां से डिमांड मंगा कर उपलब्ध करा दी है।

जो लोग आज तक यह समझते थे कि असम और बंगाल में सिर्फ धान होता है वहां आज अच्छे किस्म के और ज्यादा गेहूं पैदा होने लगा है जितना जालंधर और लुधियाना में होता है। यह हमने प्रयत्न किया है। यही मैं सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि खाद बीज और आवश्यक क्रैडिट सभी सरकारों को उपलब्ध करा दिया गया है। जिन्होंने कुछ और क्रैडिट मांगा, ऋण मांगा उसके लिए भी हमने बैंक से लिखा-पढ़ी की प्रबन्ध कराने के लिए। हम यह चाहते हैं कि रबी की फसल की बुवाई समय पर हो जाए। कुछ किस्म के गेहूं हैं जिनको नवम्बर में बो दिया जाता है, कुछ किस्म ऐसी हैं जिनको दिसम्बर के अंत तक चलाया जा सकता है और कुछ किस्म ऐसी हैं जिनको जनवरी के पूर्वार्द्ध में ले जाया जा सकता है। रबी की बुवाई अच्छी होगी इस पर पूरा भरोसा है। मैंने कहा कि हमने कभी खाद्य के मामले में राजनीति की बात नहीं सोची है। पिछली दफा जब मैं

5p.m. खाद्य मंत्री था तो बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार थी। अगर नीरेन बाबू उस वक्त के जो मुख्य मंत्री थे उनसे पूछेंगे तो उनको मालूम होगा कि हमारी तरफ से सहायता और सहयोग में कोई भी शिकायत की गुंजायश नहीं थी।

SHRI NIREN GHOSH : This much I must say that some Ministers came here to offer dharna for food.

श्री जगजीवन राम : एक बात मैं और कहना चाहता हूं। मैं यह कहूं कि मैं डिसक्रिमिनेशन करूंगा और डिसक्रिमिनेट करना भी चाहूं तो मैं वह कर नहीं सकता क्योंकि अगर कोई कहे कि किसी दुकान पर कांग्रेस वालों को अनाज नहीं मिलेगा तो यह नहीं हो सकता। इसलिए पोलिटिकल डिसक्रिमिनेशन की बात करना, खासतौर से खाद्य के मामले में, मैं समझता हूं कि जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं, वे अपनी अक्ल को बाहर छोड़कर आते हैं। यह हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमको ऐसे मामलों में राजनीतिक से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। हो सकता है कि जो लोग इस प्रकार की बातें कहते हैं उनको और उनकी पार्टी को इसमें कुछ शक्ति मिल सकती है, लेकिन यह क्षणिक शक्ति होगी, वह टिकाऊ शक्ति नहीं होगी।

अभी श्री नीरेन बाबू ने भूख से मरने वालों के आंकड़े दिये हैं और बारबार उनको दोहराया है। मैं कहता हूं कि आप 25 हजार केसेज में ढाई सौ लोगों के नाम लेकर कह दीजिए कि फलां फलां गांव में अनाज के अभाव से लोग मरे हैं तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि उस वक्त उस गांव के इर्दगिर्द अनाज था या नहीं था। अगर अनाज था तो अनाज के बिना किस प्रकार लोग मर गये। लेकिन आज स्थिति यह है कि हमारे देश के पढ़े-लिखे लोगों के मन में यह बात घर कर गई कि अनाज ही पहले आवश्यक है। मैं समझता हूं कि पहली आवश्यक चीज व्यक्ति की परचेजिंग पावर है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा गरीब देश है। बहुत नार्मल टाइम में, साधारण स्थिति में भी इन बातों से लोगों को तकलीफ रहती है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। हम लोग उसी काम में लगे हुए हैं कि हमारे देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो। हमारा किसी दल से या किसी पार्टी से राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन इसमें कोई मतभेद की गुंजायश नहीं है कि हमें भारत को समृद्धशाली और शक्तिशाली देश बनाना है।

श्री महावीर त्यागी : इसमें यह तमाम पार्टियां आपका साथ देंगी।

श्री जगजीवन राम : हम इसका बिलकुल स्वागत करते हैं। श्री नीरेन घोष ने पंडित जवाहर लाल नेहरू का जिक्र किया और साथ ही यह भी कहा कि वे आपके नेता थे, हमारे नेता नहीं थे। नीरेन बाबू, भारत में आपको नेता नहीं मिल सकता है।

SHRI NIREN GHOSH : I will not go and search for leaders inside the Congress. Never, you can rest assured on this.

SHRI JAGJIVAN RAM: I am just interpreting what you have said and it fits on you.

SHRI NIREN GHOSH : You seek your ideological inspiration from America and England. Let me remind you of that also.

श्री जगजीवन राम : मैं आपकी बातों की व्याख्या कर रहा था, और कुछ नहीं कह रहा था । भारत की एक गरिमा रही है और हम इस प्रयत्न में लगे हुए हैं कि वह दिन शीघ्र आ सके जब हम सिर उठाकर कह सकें कि आज हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको खाना न मिला हो या जो रात को खाना खाकर नहीं सोया है, किसी को कपड़े का अभाव नहीं हो, मकान का अभाव नहीं हो, किसी को शिक्षा का अभाव नहीं हो । लेकिन साथ ही हमें यह कहने में भी संकोच नहीं है कि हम इसको अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं । आज भी देश में बहुत लोग हैं जिनको समय पर भरपेट खाना नहीं मिलता है, जिनको जरूरत भर कपड़ा नहीं मिलता है । हम चाहते हैं कि यह स्थिति जल्दी से जल्दी दूर हो । उपसभापति महोदय, यहां पर कहा गया था कि इस मामले में सभी लोगों की राय होनी चाहिए । मेरा ऐसा विचार है कि हम एक अखिल भारतीय स्तर पर एक फूड एडवाइजरी कौंसिल बनायें जिसमें माहिर लोगों को रखा जाय पब्लिकमैनों को रखा जाय और सभी की सलाह और राय इसमें ली जाय । मैं समझता हूं कि खाद्यान्न समस्या को छिपाने की बात नहीं है । हमारे देश की जो स्थिति है, हमारे देश में जो संकट है, उसमें हम आप सब का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम मिलकर इस संकट को जितना हल्का बना सकें, हल्का करें । वाणी से संकट हल्का बनाया जा सकता है और वाणी से ही संकट को गम्भीर भी बनाया जा सकता है ।

मैंने कहीं कहा था, याद नहीं कहां, कि हमारे देश में कम से कम 12 करोड़ परिवार होंगे; अगर हम अभाव की स्थिति पैदा करते रहें और ये 12 करोड़ गृहिणियां और कुछ नहीं करें, दस-दस किलो अपने पास रख लें, तो 12 लाख टन हो जाएगा । 12 लाख टन अगर इम्मोबिलाइज हो जाएगा तो अभाव की स्थिति पैदा हो सकती है इसलिए मैंने गृहिणियों से अनुरोध किया था कि खरीद कर के अपने घर में अन्न भण्डार नहीं बनाओ उससे परेशानी बढ़ेगी । इसलिए मैंने कहा कि खाद्य का प्रश्न एक बहुत नाजुक प्रश्न है, बहुत डेलिकेट है, इसलिए कोई काम या किसी तरह का कहना ऐसा नहीं होना चाहिए । जो अभाव की आबोहवा को और भी गम्भीर बना दे । तो मैंने इस बहस का स्वागत किया है, आप लोगों ने जो राय दी है कृषि में सुधार करने की दृष्टि से . . . .

श्री महावीर त्यागी (उत्तर प्रदेश) : एक बार फिर विश्वास दिलाता हूं, विरोधी दल पूरी तरह से आपके साथ इस मामले में सहयोग करेगा ।

श्री जगजीवन राम : आप तो हमारे साथ ही बराबर रहें, उस तरफ बैठ गए तो क्या हुआ ? भाई, आप उस तरफ भी बैठ गए तो रक्त आपके बदन में वही तो है । मैं फिर दुहराऊंगा उपसभापति जी, कि खाद्य के प्रश्न को राजनीति का प्रश्न बनाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए । खाद्य के संकट की वजह से लोगों को जो परेशानी होती है उस परेशानी को लेकर सत्तारूढ़ सरकार को मारने का प्रयत्न भी नहीं होना

चाहिए, हालांकि उस मार में कोई बात नहीं रहती है . . .

श्री महावीर त्यागी : आपकी प्राइम मिनिस्टर बधाई के योग्य हैं इसलिए कि आपको उन्होंने यह महकमा दिया है। यह वाकई बड़ा अच्छा काम किया है वरना खतरे में थे हम सब।

श्री जगजीवन राम : मेरा भी यह सौभाग्य है त्यागी जी, देश में कठिन से कठिन काम जब मैंने लिया है तो आप लोगों का सहयोग चाहा है और इस बार भी इन जिम्मेदारियों को लिया तो इसी भरोसे पर लिया कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि देश की जनता चाहती है कि मैं उस जिम्मेवारी को लूं। सब का सहयोग मिला है। मुझे भरोसा है कि सब के सहयोग से देश को इस संकट की घड़ी से हम निकाल सकेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11.00 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at eight minutes past five of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 27th November, 1974.

MGIPRRND—81 RSS/74—IID/S—14-2-75—595.